



वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-308

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र
ग्रामीण दैनिक

जम्मू तवी, मंगलवार 16 दिसम्बर, 2025

मूल्य-3 रुपये- (लेह) 4 रुपये

पृष्ठ -8

देहात संदेश



Polio Day
21 December 2025
Sunday
In all districts
Ensure every child under 5 years of age gets polio drops everytime

पल्स पोलियो अभियान
"दो बूंद जिंदगी की"
हर बच्चे का अधिकार, पोलियो
ड्रॉप से सुरक्षा अपार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू एवं कश्मीर

@diprjk @dipr_jk @informationprjk Information & PR, J&K

DIP/J-9034/25
Dtd: 15-12-2025

लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी

श्रीनगर, 15 दिसंबर। लोकसभा ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी, जिसमें अतिरिक्त 41455 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से 2504 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए रखे गए हैं, जिन्हें दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच देनदारियों के बंटवारे के कारण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को ट्रांसफर किया जाएगा। अनुदान की अनुपूरक मांगों के अनुसार, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच देनदारियों के बंटवारे के कारण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को ट्रांसफर करने के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए लद्दाख को 2504.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। J&K और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तय की गई देनदारियों के बंटवारे के अनुसार, J&K के पूर्व राज्य की कुल देनदारियों का दो प्रतिशत - 2504.46 करोड़ रुपये - लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को



ट्रांसफर किया गया।

अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, भारत सरकार ने पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरुण गोयल और सेवानिवृत्त भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी गिरिराज प्रसाद गुप्ता को मिलाकर एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था, ताकि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संपत्तियों और देनदारियों के वितरण पर काम किया जा सके। समिति ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम,

2019 की धारा 84 और धारा 85 के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में दो हिल काउंसिलों के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के लिए 148.64 करोड़ रुपये और जम्मू में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को ट्रांसफर करने के लिए अतिरिक्त खर्च के रूप में 20.14 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

मंत्रालय ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त खर्च

पुनर्गठन देनदारियों के लिए लद्दाख को 2504 करोड़ रुपये हिल काउंसिलों को अतिरिक्त 148 करोड़ रुपये मिलेंगे
J&K को 624-MW किरू, JTFR परियोजनाओं के लिए 340 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले

को पूरा करने के लिए 12.04 करोड़ रुपये और दूरदर्शन के इलाकों में बिजली उत्पादन के लिए बिजली खरीद और डीजल की खरीद के लिए 3 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी रखा है। जम्मू और कश्मीर के लिए, मंत्रालय ने 624 MW किरू प्रोजेक्ट और झेलम तवी फलड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए इकट्टी योगदान की तरफ अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 340.15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा, 'इंडिया' गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं : उमर



जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे से सोमवार को खुद को अलग कर लिया और कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) और निर्वाचन आयोगों पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी सत्ताधारी पार्टी के डीएनए में है और उसके नेता गद्दार हैं जो लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने की साजिश रच रहे हैं और उन्हें सत्ता से हटाया जाना चाहिए। अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल

इन्क्लूसिव अलायंस' ('इंडिया') गठबंधन में एक घटक है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी और कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, 'इंडिया' गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हर राजनीतिक दल को अपना एजेंडा तय करने की स्वतंत्रता है। कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हम उन्हें कुछ कहने वाले कौन होते हैं? कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने वोट चोरी के खिलाफ लगभग छह करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए हैं और वह इन्हें भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगी।

खबर संक्षेप

युवक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला

जम्मू, 15 दिसंबर। जम्मू आरएसपुरा में दो युवकों ने एक युवक का रास्ता रोक उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को लोगों के सहयोग से सब जिला अस्पताल आरएसपुरा में पहुंचाया गया। उपचाराधीन की पहचान मनोज कुमार उर्फ मोजा निवासी वार्ड नं. 4 आरएसपुरा के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों की मानें तो यह हमला करने वालों की पहचान अनिल कुमार उर्फ आशु निवासी वार्ड नं. 7 आरएसपुरा व अनिल कुमार उर्फ नंदी निवासी वार्ड नं.9 आरएसपुरा के रूप में की गई है। घायल के ब्यानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वेटलैंड परियोजना के नाम पर भूमि कब्जे का आरोप

जम्मू, 15 दिसंबर। परगवाल क्षेत्र में प्रस्तावित वेटलैंड परियोजना को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परियोजना के नाम पर करीब 90 हजार कनाल भूमि को चिह्नित किया गया है जिसकी आड़ में किसानों की निजी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम किसानों को हाशिये पर धकेलने और उनकी आजीविका खत्म करने की कोशिश है।

ग्रामीणों के अनुसार परगवाल तहसील के अंतर्गत आने वाले लगभग 25 से 30 गांव इस परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं जिससे हजारों किसानों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने किसानों की मालिकाना भूमि की सुरक्षा और प्रस्तावित वेटलैंड परियोजना की गहन समीक्षा की मांग की है।

सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में नियुक्त 103 दमकल कर्मियों की सेवाएं की समाप्त

श्रीनगर, 15 दिसंबर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (एफ एंड ईएस) विभाग में नियुक्त 103 दमकलकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह कार्रवाई एक जांच और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) की छानबीन के बाद की गई है जिसमें 2020 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और हेराफेरी पाई गई थी। सरकारी आदेश संख्या 608-गृह, 2025 दिनांक 15 दिसंबर के अनुसार यह कार्रवाई 2022 में गठित एक जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के बाद की गई है जिसने कागजों के रिसाव, ओएमआर शीट में छेड़छाड़, योग्यता सूची में हेराफेरी और चयन प्रक्रिया में अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच की थी। आदेश के अनुसार जांच में अपराधिक जांच की सिफारिश की गई जिसके बाद एसीबी ने एफआईआर

संख्या 01/2025 दर्ज कर विस्तृत जांच की। जांच में 106 उम्मीदवारों के पक्ष में उत्तर पुस्तिकाओं में व्यापक हेराफेरी, स्कैन की गई छवियों की जालसाजी, डिजिटल छेड़छाड़ और योग्यता सुविधों में अवैध परिवर्तन का खुलासा हुआ। यह स्थापित किया गया कि इन उम्मीदवारों को उनके वास्तविक प्रदर्शन से कहीं अधिक अंक दिए गए थे और कई लाभार्थियों ने अवैध रिश्तों के माध्यम से अंक प्राप्त किए। अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से नियुक्तियां प्राप्त करने वाले 106 उम्मीदवारों में से तीन की सेवाएं अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पहले ही रद्द कर दी गई थीं। शेष 103 नियुक्तियों को अब तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है और सरकार ने उनकी नियुक्तियों को अवैध और प्रारंभ से ही अमान्य घोषित कर दिया है।

संस्थानों में राजनीतिक दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर, 15 दिसंबर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि संस्थानों में राजनीतिक दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इससे गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। एसकेआईसीसी श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा कि कॉर्पोरेशन और विभागों के कामकाज में राजनीतिक दखलअंदाजी की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक हैं। उमर ने कहा कि राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए पहले ये संस्थान एक चुनौती हैं सरकार के प्रति जवाबदेह थे लेकिन अब उस सिस्टम के बिना फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अन्य विभागों जैसे संस्थानों को स्वतंत्र रूप से और बाहरी दबाव या राजनीतिक मकसद के बिना काम करना चाहिए। पर्यटन के मोर्चे पर उमर ने कहा कि हाल के तनाव के कारण बुकिंग रद्द हुई है लेकिन क्रिसमस और नए साल से पहले इस सेक्टर को फिर से पट्टी पर लाने के प्रयास जारी हैं उन्होंने कहा कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही श्रीनगर में अपना सालाना कन्वेंशन आयोजित करेगा जो एक सकारात्मक कदम है।

मुख्य सचिव अटल इलु ने डीपीआईआईटी की ईज ऑफ इडिंग बिजनेस पहल के अंतर्गत नवगठित डी-बीआरएपी के कार्यान्वयन की समीक्षा की

जम्मू, 15 दिसंबर मुख्य सचिव अटल इलु ने आज भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ईज ऑफ इडिंग बिजनेस पहल के अंतर्गत नवगठित जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डी-बीआरएपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित इस समीक्षा बैठक में प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ-साथ सभी जिलों के उपायुक्तों ने व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।



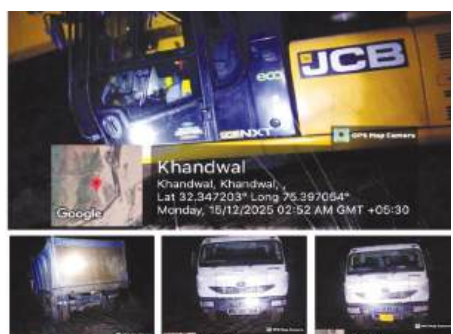
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने डी-बीआरएपी के अंतर्गत अनिवार्य विभागवार सेवाओं और सुधार मापदंडों का व्यापक मूल्यांकन किया। उन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा एक साझा

रीयल-टाइम डैशबोर्ड विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो सभी विभागों और जिलों में सभी सेवाओं की स्थिति का समेकित दृश्य प्रदान करे। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम

पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सभी सेवाओं को अनिवार्य रूप से एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के साथ एकीकृत किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत लंबित सेवाओं को स्पष्ट समयसीमा के साथ अधिसूचित करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि ये सेवाएं डी-बीआरएपी ढांचे के तहत परिकल्पित ऑनलाइन माध्यमों से प्रदान की जाएं।

अवैध खनन/परिवाहन में लिफ्ट 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन जब्त



कटुआ, 15 दिसंबर। जिले में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एसएसपी कटुआ मोहिता शर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में कटुआ पुलिस ने नगरी, हटली, रामकोट और हीरानगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में

निर्माण सामग्री के अवैध परिवहन के लिए कुल 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। प्रथम मामले में उपायुक्त मुख्यालय कटुआ और पुलिस स्टेशन कटुआ के एसएसपी की देखरेख में प्रभारी पुलिस अधिकारी नगरी और प्रभारी पुलिस अधिकारी हटली के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त के दौरान 3 डंपर जेके08एन-4725, पीबी13बीएस-7744, एक अज्ञात पंजीकरण संख्या वाला वाहन और 1 जेसीबी मशीन जब्त की जो बिना किसी कानूनी अनुमति के निर्माण सामग्री के अवैध खनन/परिवहन में लिप्त थे। दूसरे मामले में प्रभारी पुलिस स्टेशन रामकोट के नेतृत्व में पुलिस दल ने अवैध खनन में शामिल एक डंपर जेके14ई-9553 को जब्त किया। इस डंपर का फॉर्म वैध था लेकिन इसमें ए फॉर्म की सीमा से अधिक सामग्री भरी हुई थी। इसे गलाक क्षेत्र में जब्त किया गया था।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बादल छाए रहने से रात के तापमान में मिली थोड़ी राहत

श्रीनगर, 15 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बादल छाए रहने से रात के तापमान में थोड़ी राहत मिली लेकिन ठंड बनी रही। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में अभी भी लगभग जमा देने वाला और जमावट बिंदु से नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि काजीगुड और पहलगाम में 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कुपवाड़ा में 1.6 डिग्री सेल्सियस, काकरनाग में 2.4 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया

गया। पोंपोर में 0.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर एयरपोर्ट पर 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अवंतीपोरा में तापमान गिरकर शून्य से नीचे 0.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। शोपियां में भी शून्य से नीचे 0.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी जगहों पर बड़गाम में 1.0 डिग्री सेल्सियस, अनंतनाग में 1.3 डिग्री सेल्सियस, बारामूला में 0.9 डिग्री सेल्सियस, बांदीपोरा में 2.7 डिग्री सेल्सियस, कुलगाम में 2.5 डिग्री सेल्सियस, गांदारबल में 2.3 डिग्री सेल्सियस और सोनमर्ग में 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोपपत्र किया दाखिल

श्रीनगर, 15 दिसंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें इस साल 22 अप्रैल को 26 नागरिक जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, मारे गए थे। इस मामले में तीन मृत आतंकवादियों सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में साढ़े सात महीने बाद आतंकी हमले के मामले में आरोपपत्र में नामजद किया है। आरोपपत्र में हमले में शामिल तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी शामिल किया गया है जो बाद में श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में मारे गए थे। इन आतंकवादियों में सुलेमान शाह, हमजा और जिब्रान शामिल हैं। हमले से एक दिन पहले आतंकवादियों को रसद सहायता,



आश्रय और भोजन मुहैया कराने वाले दो और ग्राउंड वर्क्स (ओजीडब्ल्यू) का नाम भी आरोपपत्र में शामिल है। इनमें बशीर अहमद जोधर और परवेज़ अहमद शामिल हैं। एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल करते समय विशेष अदालत में मृतकों के रक्त के नमूने और बालों के रेशों की सबूत के तौर पर पेश किए इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के एक समूह पर किए गए हमले में कम से कम 26 नागरिक मारे गए



शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई-पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए जापान की सकनीरा एसोसिएशन द्वारा पानी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पानी के द्वारा रोगों को दूर करने की यह सादी-सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है।

सेहत का राज

बस 4 ग्लास पानी एक साथ

सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, मोटापा, बेहोशी, दमा, खांसी, लीवर की कमजोरी, पेशाब की बीमारी, गैस, कब्ज, एसीडिटी, कमजोरी, आंख की बीमारी, मानसिक रोग, महिलाओं को होने वाली बीमारियां एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई-पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए जापान की सकनीरा एसोसिएशन द्वारा पानी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पानी के द्वारा रोगों को दूर करने की यह सादी-सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है। कमी है तो बस इसके जनसाधारण के बीच प्रसार की।

पानी प्रयोग की विधि क्या है

सुबह उठकर बिस्तर में बैठ जाए और चार बड़े ग्लास भरकर (लगभग एक लीटर) पानी एक ही समय एक साथ पी जाए। ध्यान रहे कि पानी पीने के पहले मुंह न धोए, न ब्रश करें तथा शौचकर्म भी न करें। पानी पीने के बाद थूकें नहीं। पानी पीने के पौन घंटे बाद आप ब्रश/दातून, मुंह धोना, शौचकर्म इत्यादि नित्यकर्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार या कमजोर काया के हैं और वे एक साथ चार ग्लास पानी नहीं पी सकते तो उन्हें शुरुआत एक-दो ग्लास पानी से करना चाहिए तथा धीरे-धीरे चार ग्लास तक बढ़ाना चाहिए। साथ ही भोजन करने के बाद लगभग दो घंटे पानी न पिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। चार ग्लास पानी पीने की यह विधि स्वस्थ या बीमार, सभी के लिए अति लाभदायक सिद्ध हुई है। सकनीरा एसोसिएशन के अनुभव द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि कई बीमारियां इस प्रयोग से निम्नलिखित समय में दूर होती जाती हैं।

- मधुमेह एक माह के लगभग।
- उच्च रक्तचाप एक माह के लगभग।
- गैस दो सप्ताह के लगभग।
- टी.बी. छः माह के लगभग।
- कब्जीयत- दो सप्ताह के लगभग।

सावधान रहें ताजातरीन सब्जियों से

यू तो हम हर रोज तरह-तरह की सब्जियां खाते हैं लेकिन वे ताजा होती हैं इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हर रोज सामने आ रही बीमारियों के पीछे कहीं न कहीं एक कारण यह भी है कि आज इसान को शुद्ध और ताजा आहार नसीब नहीं हो पा रहा। मिलावट और रसायन संरक्षण से सब्जियां भी अछूती नहीं हैं।

सब्जी विक्रेता आज या तो रसायन में संरक्षित कर रखी गई सब्जियां बेचते हैं या फिर मुनाफे के चक्कर में लोकी जैसी सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं। आहार विशेषज्ञ का कहना है कि लोगों को अपने आहार में ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए जो बहुत दिनों से संरक्षित कर रखी गई हों। ताजा सब्जियां जहां खाने में स्वादिष्ट और पोषिक होती हैं वहीं उनमें विटामिन काबोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन सावधानी यह जरूरी है कि सब्जियां सवमुच ताजा हो न कि उन्हें इंजेक्शन से ताजा बनाया गया हो। बाजार से सब्जियां खरीदते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यदि ऐसी सब्जी खरीद ली जाती है, जिसका आकार बढ़ाने के लिए या चमकदार दिखाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल किया गया हो तो इससे पेट में अल्सर अम्लता और गैस बनने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सब्जियों को संरक्षित कर रख दिए जाने

उनके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सब्जी बनाने के बाद उसे बार-बार गर्म करके रात तक इस्तेमाल किया जाता रहे। ऐसा करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। एक बार सब्जी बनाने के बाद उसे कुछ घंटों के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सब्जी को फ्रिज में रख देने का मतलब यह नहीं है कि वह जरा भी खराब नहीं होगी। फ्रिज में रखी सब्जी को भी छह-सात घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद उसके पोषक तत्वों में ह्रास होने लगता है।



कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही भोजन के पाचन में भी सहायक होते हैं। इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। यदि आप सेहत के प्रति जागरूक हैं तो आपको रोजाना कम से कम एक बड़ा कप हरी सलाद खानी चाहिए।

सर्द मौसम में व्यायाम करके अपने शरीर को गर्म व ऊर्जावान बनाए रखने के साथ ही अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करना भी जरूरी हो गया है जिनकी कम मात्रा लेने पर भी शरीर को भरपूर कैलोरी मिले। पेश है 5 ऐसे आहार जो आपको सर्दियों में तरोताजा और स्वस्थ बनाएं।

सलाद
आपके सुबह व शाम के भोजन में सलाद के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। यदि आप कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला फूड लेना चाहते हैं तो सलाद आपके लिए बेहतर विकल्प है। सलाद के लिए प्रयोग में आने वाली कच्ची सब्जियों व फलों में एंटी ऑक्सीडेंट, नेचुरल एंजाइम्स और फाइबर होते हैं जो शरीर के

छिलके वाली दालें

छिलके वाली दालों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। प्रोटीन के साथ ही दालों में फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी आदि होता है। इनका सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है जिससे आपका वजन नियंत्रित होता है।

पीले व खट्टे फल

फलों में सबसे अधिक गुणकारी खट्टे फल होते हैं। पीले व नारंगी रंग के फलों में बीटा कैरोटिन व एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। खट्टे फल विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल, फाइबर आदि का प्रमुख स्रोत होते हैं जो शरीर के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। नींबू में मौजूद पेक्टिन शरीर में जमा वसा को गलाता है और पाचन प्रक्रिया को भी धीमा करता है जिससे खाने के बाद भी लगने वाली भूख शांत होती है। खट्टे फलों का सेवन डाइबीटिज, कैंसर, एनीमिया, मोतियाबिंद, अस्थमा, किडनी में पथरी आदि रोगों में लाभदायक होता है। इन फलों को निरंतर सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है।

तरल, जूस व ड्रिंक

भोजन के पूर्व या पश्चात यदि आप तरल पदार्थ लेने के आदी हैं तो इस सर्द मौसम में भी आप छाछ, लस्सी, दही व फ्रूट जूस का सेवन कर सकते हैं। दही, छाछ व ताजे फलों का रस आपके शरीर के लिए गुणकारी होता है। खट्टे फलों में नींबू का रस वजन कम करने, डेंटल कैयर, बुखार, रक्त शुद्धि आदि में सहायक होता है। भोजन के बाद ली जाने वाली छाछ में दूध की अपेक्षा फैट की मात्रा कम होती है। यदि हम लिक्विड में नारियल पानी की बात करें तो इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, शर्करा व वसा की कम मात्रा होती है।

अंकुरित अनाज

अंकुरित किए जाने से अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा दुगुनी हो जाती है। चना, मूंग, सोयाबीन, मटर आदि को अंकुरित करके खाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में नाश्ते में अंकुरित अनाज को शामिल करना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है। भरपूर अंकुरित अनाज का सेवन आप सूख या सलाद के साथ भी कर सकते हैं। सुलभ, सस्ता, बनाने में आसान व पोषिक होने के कारण अंकुरित अनाज का सेवन आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटी ऑक्सीडेंट आदि की भरपूर मात्रा होने के कारण अंकुरित अनाज हमारे भोजन के पाचन में भी सहायक होता है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है विटामिन डी

ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी के सेवन से स्तन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। लंदन की सर्जन एवं प्रो. केफाह मोकबेल के अनुसार इससे एक हजार जिंदगियां प्रतिवर्ष बचाई जा सकती हैं। वैसे तो धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन महिलाएं अक्सर अपनी दिनचर्या में इससे महरूम हो जाती हैं। प्रो. मोकबेल का दावा है कि 20 साल की आयु के बाद महिलाएं को प्रतिदिन एक विटामिन डी की गोली का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से स्वस्थ महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका काफी घट जाती है, महिलाओं में जरूरी विटामिन डी लेबल काफी उच्च स्तर का होता है, जो अक्सर कम हो जाता है, इसे मैट्टेन करके खतरे को कम किया जा सकता है।

अध्ययन के अनुसार इसका (विटामिन डी की गोलियों का) खर्च काफी कम है और लाभ काफी अधिक क्योंकि इससे बड़ी परेशानी की आशंका काफी कम हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार, ब्रिटेन में हर साल 50 हजार महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं, इसमें 1200 मीत के मुंह में चली जाती हैं। अध्ययन के अनुसार, वैसे तो विटामिन डी हड्डियों की मजबूती में अहम रोल अदा करता है। लेकिन अब यह भी माना जाता है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने में भी लाभकारी है। यह दोनों कैंसर की रोक के अहम कारक हैं। अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल और पब्लिक हेल्थ के अनुसार विटामिन डी की कमी से कई बड़ी बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, पलू, कई प्रकार के कैंसर, टीबी और स्केरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती में अहम रोल अदा करता है यह इम्यून सिस्टम और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने में लाभकारी हेल्थ फैक्टर्स है।

जरा संभलकर मम्मी टू बी...

गर्भावस्था के दौरान जरा सी असावधानी बरतने पर आपको कमर दर्द संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए आइए जानते हैं क्या करें और क्या न करें

ऐसा न करें

- भारी वस्तुएं न उठाएं।
- कमर को झुकाएं नहीं।
- उल्टे-सीधे तरीके से न लेटें।
- जगने पर बिस्तर से झटके में न उठें।
- ज्यादा देर के लिए हाई हील न पहनें।
- कंधे पर भारी बैग लटकाकर न चलें।
- हर काम अपने सिर पर लेने की कोशिश न करें।

ऐसा करें

- भारी वस्तुएं उठाने के लिए अपने पति या अपने किसी खास से कहें।
- कमर झुकाने के बजाय घुटनों के बल बैठें और अपनी कमर सीधी रखें।
- अपनी स्प्राइन को सीधा रखने के लिए जिस करवट लेटी है उस तरफ घुटनों के बीच में एक तकिया जरूर रखें।
- नींद से उठने पर पहले करवट लें। फिर अपने हाथों का सहारा लेकर बैठ जाएं।
- हाई हील के स्थान पर लो हील और फ्लैट जूते-चप्पल का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी पेल्विस और पीठ सीधी रहेगी।
- भारी बैग के बजाय बैक पैक का इस्तेमाल करें।
- जितना संभव हो घर के कामों की जिम्मेदारियां परिवार के सदस्यों को सौंपें। आपके साथ ही आने वाले नन्हें मेहमान को भी तो सुकून चाहिए।



यूटी स्तरीय अंडर-19 बॉयज़ सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट का समापन, फाइनल में जम्मू ने श्रीनगर को 4-2 से हराकर खिताब जीता



जम्मू, 15 दिसंबर (हि.स.)। युवा सेवा एवं खेल विभाग, रियासी द्वारा आयोजित यूटी स्तरीय इंटर-डिस्ट्रिक्ट अंडर-19 बॉयज़ सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट का श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कटरा में समापन हुआ।

रोमांचक फाइनल मुकाबले में जिला जम्मू ने जिला श्रीनगर को 4-2 से पराजित कर

चैंपियनशिप अपने नाम की। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी रियासी, तरसेम सिंह ने मुख्य अतिथि, भाग लेने वाली टीमों और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने जानकारी दी कि इस टूर्नामेंट में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों के कुल 600 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो

युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है।

उन्होंने टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सहयोग की सराहना करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार और निदेशक खेल, एसएमवीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ध्रुव गुप्ता का आभार जताया। साथ ही मुख्य अतिथि संजीव कोतवाल का धन्यवाद किया, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैचों का संचालन अनुभवी अधिकारियों ओपिंदरपाल सिंह, मदन मोहन, राकेश सिंह, एस.एस. सोदी, धीरज सिंह और राकेश कुमार शर्मा ने किया। समापन अवसर पर विभागीय अधिकारी, कोच, खिलाड़ी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आरएसपुरा पुलिस स्टेशन ने हत्या के मामले को 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

जम्मू, 15 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू के आर.एस. पुरा पुलिस स्टेशन द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में शामिल अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया जम्मू की नीलम कुमारी पत्नी बलबीर कुमार निवासी तलहार तहसील अरनिया जिला जम्मू ने आरएसपुरा के कोटली गाला बाना स्थित मोटेसरी स्कूल के पास अपने भाई मनोज कुमार उर्फ मोजा की हत्या के प्रयास के संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी आशु चौधरी और करण कुमार उर्फ अनिल कुमार उर्फ नंदी ने धारदार हथियारों से लैस होकर उसके भाई को रोका और उस पर जानलेवा हमला किया जो स्पष्ट रूप से आपराधिक साजिश और इरादे को दर्शाता है। अपराध का गंभीर संज्ञान लेते हुए आरएसपुरा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और

एसएचओ की देखरेख में विशेष टीमें गठित कीं।

तकनीकी और जमीनी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों का पता लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। 24 घंटे के भीतर दोनों मुख्य आरोपी आशु चौधरी और करण कुमार उर्फ अनिल कुमार उर्फ नंदी को आरएस पुरा इलाके से सफलतापूर्वक दृढ़कर गिरफ्तार कर लिया गया जिससे आगे की आपराधिक गतिविधियों को नाकाम कर दिया गया। यह बताना महत्वपूर्ण है कि दोनों आरोपी कुख्यात अपराधी हैं और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के कई मामले पहले से दर्ज हैं।

व्यापक आपराधिक कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। जम्मू पुलिस कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है।

हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 15 दिसंबर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 'जनता दर्शन' के जरिए प्रदेशवासियों से मिलकर सीधे उनकी समस्या सुनने और उसके निराकरण की पहल निरंतर जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भी 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक फरियादी से मिले, समस्याएं सुनीं। सभी का प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को सख्त व उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। "अन्नदाता किसान की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार" जनता दर्शन 'में पीएसी के सिपाही ने अपनी समस्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए मामले के उचित निस्तारण का निर्देश दिया। शाहजहांपुर से आए किसान ने मुख्यमंत्री जी से धान खरीद केंद्र की लापरवाही की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, शासन-प्रशासन के



अधिकारी इसका ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जी ने शाहजहांपुर के डीएम को निर्देशित किया कि ऋय केंद्रों का औचक निरीक्षण करें। किसी भी केंद्र पर धान ले जाने वाले किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से भी कुछ फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री संबंधित मामले में प्रयागराज के जिला व पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि इन समस्याओं का निस्तारण कराएं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार पहले

दिन से ही लोगों की सेवा, सुरक्षा व सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। साढ़े 8 वर्ष में जनता की समस्या सुनने और उसके निराकरण के लिए सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही है। सीएम ने 'जनता दर्शन' में आए लोगों को आश्वासन दिया कि हर समस्या का उचित निस्तारण कराएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से नाम पूछा, चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ने करने को कहा। सीएम ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद

गतका में नए मानक स्थापित ; नेशनल गतका एसोसिएशन ने प्रमाणन ज़रिए ऑफिशिएटिंग स्तर को उठाया ऊँचा

चंडीगढ़, 15 दिसंबर। तीन दिवसीय राष्ट्रीय गतका रिफ़ेशर कोर्स का समापन नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एन.जी.ए.आई.) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के साथ प्रभावशाली ढंग से हुआ। यह परीक्षा पारंपरिक मार्शल खेल गतका में ऑफिशिएटिंग मानकों को पेशेवर रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रही है। इस परीक्षा के आधार पर गतका अधिकारियों की ग्रेडिंग और प्रमाणन किया गया जो आगे चलकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में ऑफिशिएटिंग की पात्रता प्रदान करेगा।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए एन.जी.ए.आई. के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि यह प्रमाणन प्रक्रिया नियमों की एकरूप व्याख्या सुनिश्चित करने, तकनीकी दक्षता को मजबूत करने और प्रतियोगिताओं के दौरान अनुशासन एवं निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब केवल वही रेफरी और जज, जिनका संरचित सैद्धांतिक और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से प्रमाणन किया गया है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और प्रमुख प्रतियोगिताओं में ऑफिशिएटिंग की ज़िम्मेदारी निभाएंगे।

गतका प्रमोटर ग्रेवाल ने बताया कि यह



रिफ़ेशर कोर्स और परीक्षा गतका ऑफिशिएटिंग को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाने की घोषणा की कि अगला राष्ट्रीय गतका रिफ़ेशर कोर्स जनवरी में छत्तीसगढ़ के भिलाई में न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ग्रेवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित और प्रमाणित अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में ग्रेवाल ने बताया कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन की अंतरराष्ट्रीय नियम पुस्तिका का संशोधित पाँचवाँ संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अद्यतन संस्करण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

प्रतियोगिताओं से प्राप्त हालिया सुधारों और व्यावहारिक अनुभवों को समाहित करेगा तथा खिलाड़ियों, अधिकारियों और आयोजकों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा।

विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी सीखने का अवसर बताया। छत्तीसगढ़ के अमन सिंह, महाराष्ट्र के पांडुरंग अंबुरे, पंजाब के गुरविंदर सिंह घनौली और हरियाणा के हरनाम सिंह ने कहा कि विस्तृत सैद्धांतिक जानकारी और व्यावहारिक सत्रों के संयोजन से उन्हें ऑफिशिएटिंग प्रोटोकॉल, प्रतियोगिता प्रबंधन और मैदान पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है।

वर्ल्ड गतका फेडरेशन की नियम पुस्तिका का संशोधित संस्करण जल्द होगा जारी – ग्रेवाल तीन दिवसीय राष्ट्रीय रिफ़ेशर कोर्स के समापन के साथ गतका ऑफिशिएटिंग में नई दिशा

इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुखचैन सिंह कलसानी ने कहा कि एन.जी.ए.आई. ने गतका में संरचित शासन व्यवस्था, जवाबदेही और पेशेवर दृष्टिकोण की ओर स्पष्ट संकेत दिया है जिससे आने वाले वर्षों में अधिक अनुशासित और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रतियोगिताओं का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर एन.जी.ए.आई. के महासचिव हरजिंदर कुमार और गतका एसोसिएशन ऑफ़ पंजाब के संयुक्त सचिव बलजीत सिंह ने भी गतका के बढ़ते राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विस्तार के साथ कदम मिलाने के लिए निरंतर क्षमता-विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

पुलिस ने नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत डोरु पुलिस स्टेशन में नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

अनंतनाग, 15 दिसंबर (हि.स.)। अनंतनाग पुलिस ने नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत डोरु पुलिस स्टेशन में नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आम जनता विशेषकर युवाओं को नशाखोरी के हानिकारक प्रभावों और स्वस्थ नशामुक्त जीवन जीने के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों युवाओं और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया पुलिस अधिकारियों ने नशाखोरी के सामाजिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों पर प्रकाश डाला और नशाखोरी की रोकथाम में परिवारों और समाज की भूमिका पर जोर दिया। प्रतिभागियों को नशाखोरी की शीघ्र पहचान एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी परिणामों और पुनर्वास एवं नशामुक्ति सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने युवाओं से खेल शिक्षा और कौशल विकास जैसी रचनात्मक गतिविधियों में अपनी ऊर्जा लगाने का आग्रह किया।

उन्होंने आम जनता से अपने क्षेत्रों में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से संबंधित जानकारी साझा करके पुलिस के साथ सहयोग करने की भी अपील की।

सुनील शर्मा की संगठनात्मक ताकत भाजपा की असम चुनाव रणनीति को बढ़ावा देगी : बिलवारिया

जम्मू, 15 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेतृत्व ने बलदेव सिंह बिलवारिया महासचिव जम्मू-कश्मीर भाजपा के नेतृत्व में आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को भाजपा आलाकमान द्वारा असम विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव सह-प्रभारी के रूप में उनके नामांकन पर सम्मानित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए बलदेव सिंह बिलोरिया ने सुनील शर्मा को बर्बाद दी और पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण, अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की।

उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा ने लगातार तीव्र राजनीतिक कौशल, रणनीतिक स्पष्टता और जमीनी स्तर पर पार्टी

कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि संगठन में सुनील शर्मा की यात्रा अथक परिश्रम, संगठनात्मक निष्ठा और पार्टी केडर के साथ गहरे जुड़ाव द्वारा चिह्नित की गई है।

बिलवारिया ने कहा, चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों को परिपक्वता और दूरदर्शिता के साथ संभालने का उनका अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए स्वाभाविक पसंद बनाता है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि शर्मा का अनुशासित, परिणामोन्मुख दृष्टिकोण और व्यावहारिक संगठनात्मक शैली असम में भाजपा की चुनाव तैयारियों को काफी मजबूत करेगी।

जीजीएम साइंस कॉलेज में विश्व एड्स दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन



जम्मू, 15 दिसंबर (हि.स.)। जीजीएम साइंस कॉलेज, जम्मू के रेड रिबन क्लब द्वारा विश्व एड्स दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 15 दिसंबर को एक जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज की विश्व एड्स दिवस से जुड़ी दूसरी प्रमुख गतिविधि रहा, जिसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स के खिलाफ समुदाय-नेतृत्व वाले प्रयासों के महत्व को रेखांकित करना

2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पुन कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ। वॉकथॉन के दौरान प्रतिभागियों ने प्रभावशाली नारों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया। रेड रिबन थीम पर आधारित पोस्टरों में रोकथाम के उपाय, जांच की आवश्यकता और एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी की उपलब्धता को सरल व प्रभावी ढंग से दर्शाया गया, जिससे यह पहल एक सफल शैक्षणिक अभियान के रूप में उभरी। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) रोमेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन और डॉ. रोजी बंबा की संयोजकता में किया गया। आयोजन को सफल बनाने में प्रो. सुरिंदर कुमार, डॉ. मकीम अंसारी, डॉ. रोहित भारद्वाज, प्रो. विशाल शर्मा और डॉ. मुजफ्फर अहमद शेख का विशेष योगदान रहा।

भाजपा महिला मोर्चा ने सशक्त आर्थिक दृष्टिकोण का आह्वान अजोगित किया



जम्मू, 15 दिसंबर (हि.स.)। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा उत्तर जिला ने मारह मंडल के श्यामपर्वक गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष एडवोकेट नेहा महाजन महासचिव इंजीनियर उशीशी गुप्ता और पूनम गुप्ता उपाध्यक्ष संतोष शर्मा और सचिव सुपन रेना ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मंडल सरपंच ज्योति के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की उतर जिला अध्यक्ष अंजली शर्मा चौहान ने की। एडवोकेट नेहा महाजन ने आत्मनिर्भर भारत पहल

के उद्देश्यों पर चर्चा की। जिसमें स्वरोजगार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों अर्थव्यवस्था अवसरवना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग - की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। नेहा महाजन ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिस्थापन उपायों पर जोर दिया साथ ही सुरक्षा अनुपालन और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं में सुधार करके वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा।



GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
MECHANICAL & HOSPITAL DIVISION
KATHUA



Extension Corrigendum1
Name of Work: Design Fabrication Providing Installing Testing and Commissioning of 02 Nos Hospital stretcher cum passenger elevator of machine room less MRL arrangement type at newly constructed 200 bedded block G plus 3 in Associated Hospital Government Medical.
Tender ID :2025_PWDJK_297193_1
Reference: e-NIT No MHDK/TECH/e-NIT/ 2025-26/57 dated 03/12/2025
Due to poor response the e-NIT No MHDK/TECH/e-NIT/ 2025-26/57 dated 03/12/2025 issuedfor the work **"Design Fabrication Providing Installing Testing and Commissioning of 02 Nos Hospital stretcher cum passenger elevator of machine room less MRL arrangement type at newly constructed 200 bedded block G plus 3 in Associated Hospital Government Medi"** is hereby extended up to 18/12/2025 till 11.00 am and shall be opened on 18/12/2025 at 03.00 pm. The revised critical dates can be seen/ downloaded from the J&K Govt. website www.jktenders.gov.in.
Rest all other terms and conditions of e-NIT shall remain the same
No: - MHDK/Tech/3421-22
Dated: 13/12/2025

DIP/J-9016/25
Dtd: 15-12-2025

Sd/-
Executive Engineer
Mechanical & Hospital Division
Kathua

उत्तर सूचना			
ई-निविदा सूचना		दिनांक 12.12.2025	
निविदा सूचना सं. :- 433_TELE_JAT_19_25_26			
समापन तिथि /समय: 05.01.2026 15:00 बजे			
भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यरत वरिष्ठ डीएसटीई/जेएटी निविदा सूचना संख्या 433_TELE_JAT_19_25_26 के विरुद्ध https://www.ireps.gov.in पर ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। अंतिम तिथि/समय 05.01.2026 15:00 बजे है। बोलीदाता अपनी मूल/संशोधित बोलियां केवल अंतिम तिथि और समय तक ही जमा कर सकेंगे। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है, और प्राप्त ऐसे किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया जाएगा। ठेकेदारों को इस निविदा के लिए निविदा दस्तावेज लागत और बयाना राशि का भुगतान केवल आईआरडीपीएस पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से करने की अनुमति है। सिग्नाड झ्रॉफ, बैंक चेक, चेन्ना स्ट्रीट, एफडीआर आदि के माध्यम से मैनुअल भुगतान की अनुमति नहीं है।			
एनआईटी हेडर			
अनुषंग प्रकार	कार्य		
कार्य का नाम	जम्मू संभाग में जीएम निरीक्षण के लिए पीटीके-एसपीडीके खंड में सिम्लन और दूरसंचार पुनर्वास कार्य आवश्यक है।		
निविदा समापन तिथि समय	05.01.2026 15:00	निविदा अपलोड करने की तिथि समय	12.12.2025 16:42
विज्ञापित मूल्य (₹.)	4059858.3	आईआरडीपीएस के अनुसार बोली शुरू करने की तिथि	22.12.2025
व्याना राशि (₹.)	81200.00	पूरा होने की अवधि	60 Days
ग्राहकों की सेवा में सरकार के साथ			3869/25

संपादकीय

और छुट्टियों की चाहत बेतुकी

हालांकि लोकल मीडिया 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टियों को सरकार द्वारा नजरअंदाज करने के मुद्दे को उठा रहा है, जो शहीद दिवस और शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के उपलक्ष्य में थीं और 2019 के बाद खत्म कर दी गई, फिर भी, J&K में सत्ताधारी पार्टी, यानी NC, इनके फिर से शुरू होने के लिए जोरदार वकालत कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश और ज्यादा छुट्टियाँ दे सकता है, जबकि ऑफिस और कई अन्य संस्थानों को पहले से ही 40 से ज्यादा छुट्टियों का फायदा मिलता है। शिक्षण संस्थानों के मामले में, गर्मी, सर्दी और अन्य छुट्टियों के कारण छुट्टियों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाती है। इसी तरह, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थानों में, शनिवार को छुट्टी रखने से छुट्टियों की संख्या और बढ़ जाती है, जिससे काफी फर्क पड़ता है।

छुट्टियों के मामले में ऐसी उदार स्थितियों में, क्या किसी न किसी बहाने से और ज्यादा छुट्टियाँ मांगना समझदारी है? किसी मौके को मनाने के लिए छुट्टी की घोषणा करना एक अनुचित मांग है ; बल्कि, किसी घटना को मनाना या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसी प्रतिष्ठित हस्ती को उनकी जन्म या पुण्यतिथि पर सम्मान देना, ज्यादा काम करके और उस दिन को J&K, या पूरे देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव बनाकर किया जाना चाहिए।

यह सोचने और न सिर्फ शहीद दिवस या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती के मामले में, बल्कि अन्य छुट्टियों के संदर्भ में भी नज़रिए को बदलने का सही समय है। अमेरिका, इंग्लैंड और कई अन्य देशों का उदाहरण लें, जहाँ एक साल में छुट्टियों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होती है। छुट्टियों के नाम पर समय बर्बाद करना, जबकि आने वाले कामकाजी हफ्तों के लिए मन और शरीर को तरोताजा करने के लिए रविवार पहले से ही मौजूद हैं, अस्वीकार्य और अनुचित है।

यह भी समझने की ज़रूरत है कि जब बार-बार रुकावटें आम हो जाती हैं, तो विकास, शासन और सेवा वितरण प्रभावित होते हैं, क्योंकि फाइलें पेंडिंग रहती हैं, प्रोजेक्ट में देरी होती है, और जनता की परेशानी बढ़ जाती है। एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, बहुत ज्यादा छुट्टियाँ सिर्फ अक्षमता को बढ़ाती हैं और उस कार्य संस्कृति को खत्म करती हैं जो प्रगति और जवाबदेही के लिए ज़रूरी है।

यह बताना ज़रूरी है कि J&K में सरकार द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर में पूरे UT के लिए 28 सामान्य छुट्टियाँ, कश्मीर डिवीजन के लिए चार प्रांतीय छुट्टियाँ, जम्मू के लिए तीन, आठ स्थानीय छुट्टियाँ और चार प्रतिबंधित छुट्टियाँ शामिल हैं। कहा जा सकता है कि J&K के लोगों के लिए छुट्टियों का यह सिलसिला एक वजह है कि यह क्षेत्र डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी के मामलों में दूसरे क्षेत्रों से पीछे है।

पुतिन की भारत यात्रा के संदेश से बौखलाए हैं पश्चिमी देश



पुतिन की हालिया यात्रा एक दीर्घकालिक, टिकाऊ और व्यापक साझेदारी हासिल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए थी। भारत-रूस के बीच प्रगाढ़ मैत्री का संदेश देने के बाद असली चुनौती यह होगी कि यूक्रेन में आसन्न आपदा से और अधिक निराश हो रहे एवं शत्रुतापूर्ण रुख अपनाने वाले पश्चिम का सामना कैसे किया जाए। भारत पर अधिक कूटनीतिक तथा आर्थिक दबाव हो सकता है। अपनी जमीन पर खड़ा होना एक चुनौती होगी।रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही शेष विश्व से अलग-थलग करने के लिए पश्चिमी देश प्रतिबंधों और अभियानों के माध्यम से मास्को पर दबाव डाल रहे हैं। भारत पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस की निंदा करने उस देश से तेल खरीद को कम करने और फिर रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ का सामना करने का भी दबाव रहा है। ऐसे समय में जब रूस युद्ध में बढ़त हासिल कर रहा है और अधिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, पश्चिम के पास रूस को अंतरराष्ट्रीय तौर पर दूर करने के आवाशसन के अलावा यूक्रेन को देने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है। इसने ट्रम्प के शांति प्रयासों को तोड़ दिया है। इस प्रकार रूस के लिए सिर्फ युद्ध में बढ़त हासिल करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह प्रदर्शित करना है कि पश्चिम से परे एक ऐसी दुनिया है जो मायने रखती है।

ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ के देश अब तक पश्चिमी रुख से विचलित नहीं हुए हैं और उन्होंने रूस के साथ मंच साझा किए हैं। पुतिन की 4-5 दिसंबर 2025 की नई दिल्ली यात्रा इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। पश्चिम के दबाव और दंडात्मक टैरिफ के बावजूद यूक्रेन-रूस संघर्ष में किसी का पक्ष न लेते हुए रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन करना भारत के लिए अनिवार्य रहा है। अब तक एक रणनीतिक संतुलन कार्य हुआ है- रूस की निंदा न करना और शांति के बारे में बात करना। इसलिए भारत के लिए यह यात्रा केवल तेल, परमाणु ऊर्जा, श्रमिकों के प्रवास या हथियारों और लड़ाकू विमानों के बारे में नहीं थी। ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण थे और बातचीत को आगे बढ़ाया गया। इसी तरह द्विपक्षीय व्यापार में भारत के सामने आने वाले भारी व्यापार घाटे के मुद्दे पर भी विचार होना था। व्यापार असमानता को दूर करने हेतु भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए रूसी बाजारों को खोलने तथा 2030 तक भारत-रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम को अपनाने का उद्देश्य भी सामने है।

पुतिन ने इस वर्ष ही चीन (एससीओ शिखर सम्मेलन), ताजिकिस्तान (सीआईएस शिखर सम्मेलन), किर्गिस्तान (सीएसपीओ शिखर सम्मेलन) का दौरा किया। इन सभी शिखर सम्मेलनों में कई महत्वपूर्ण गैर-पश्चिमी नेताओं ने भाग लिया।

लेकिन यह अलग मामला है। पश्चिम ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पुतिन बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत में नहीं थे। वे यहाँ रूस और भारत के नेताओं के 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए थे। नई दिल्ली और माँस्को की निरंतर निकटता को लेकर पश्चिमी दुनिया की बेचैनी का पता उसकी प्रतिक्रिया से चलता है।पुतिन की भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने संयुक्त रूप से एक ऑप-एड प्रकाशित किया गया था। लेख के लहजे व समय से पता चलता था कि इन देशों ने स्पष्ट रूप से यात्रा का स्वागत नहीं किया और यूक्रेन संकट को बढ़ाने के लिए रूस को दोषी ठहराया। विदेश मंत्रालय ने इस कदम को बहुत ही असामान्य और राजनयिक मानदंडों का अस्वीकार्य उल्लंघनकरार देते हुए भारत को किसी तीसरे देश के साथ अपने संबंधों के बारे में सार्वजनिक रूप से सलाह न देने की बात कही है। रूसी राजदूत की ओर से एक विरोध पत्र जारी किया गया जिसमें कहा कि यूक्रेन समस्या 2014 में शुरू हुई जब यूक्रेनी राष्ट्रपति को १%पश्चिमी समर्थन% से अपदस्थ किया गया। पुतिन के दौरे के समय इस तरह के नकारात्मक पहलू थे लेकिन रूसी नेता के लिए रेड कार्पेट बिछया गया, भारतीय नर्तकियों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत

किया, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री की कार में एक साथ यात्रा करने का सौऑिक्स था। इसके बाद की घटनाएं संबंधों में सौहार्द और दोस्ती को प्रदर्शित करने के लिए थीं।इस यात्रा ने उम्मीदों को भी बढ़ाया। एसयू 57 लड़ाकू विमान या एस- 400/500 वायु रक्षा प्रणाली जैसी कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। लेकिन इन सौदों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इसके बजाय दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। रक्षा सौदों में समय लगता है तथा एक अलग स्तर पर बातचीत करनी पड़ती है। इसके बावजूद रूस ने भारत को परमाणु रिएक्टरों और ईंधन सहित ऊर्जा आपूर्ति के बारे में आश्वासन दिया है। श्रम गतिशीलता व वीजा सुविधा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रूस को जनशक्ति संसाधनों की आवश्यकता है एवं भारत अधिक रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान भी समझौतों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।बहरहाल, भारत-रूस संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व बुनियादी ढांचे व परिवहन गलियारों और बाजार तक पहुंच है। इस नजरिए से अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसपीसी) और यूरेशियन आर्थिक संघ के

साथ मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित करने से मदद मिलेगी। इससे अकेले रूस और कुछ सीआईएस देशों के साथ भारत के व्यापार में भारी वृद्धि होगी। संयुक्त वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि दोनों नेताओं ने भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करते हुए वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते पर चल रहे संयुक्त कार्य में तेजी लाने की सराहना की। 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि यह प्रक्रिया 2011-12 से लंबी खींची गई है और समझौते में अत्यधिक देरी हुई है।संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्ष १%स्थिर व कुशल परिवहन गलियारों के निर्माण में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए जिसमें अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसपीसी), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक (पूर्वी समुद्री) गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग का समर्थन करने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार तथा बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए रसद लिंक का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने ध्रुवीय जल में संचालित जहाजों के लिए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया।

खरपतवार -आजीविका के लिए खतरा

कुलभूषण उपमन्यु

भारत आज भी मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। देश की 48 फीसदी आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि क्षेत्र की भागीदारी 16.61 प्रतिशत है। हालांकि कृषि जनित कच्चे माल पर कई प्रकार के उद्योग भी निर्भर हैं। खासकर कपड़ा उद्योग, खांड उद्योग, पटसन उद्योग, सारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि। कहा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन का भी एक भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि भारत में पशुपालन से जुड़ी है। हर किसान पशुपालन से अतिरिक्त आय के अलावा गोबर की खाद की व्यवस्था करना चाहता है। परंपरा से पशुपालन खेती की जमीन के अलावा वन या चरागाह की जमीन पर निर्भर रहा है। किन्तु पिछले कुछ दशकों से जब से हरित क्रांति के माध्यम से विदेशी बीजों के साथ विदेशी आक्रामक खरपतवार देश में आए हैं, तब से उनका वन और चरागाह की भूमि पर फैलाव भयानक रूप ले चुका है। तैलना, युपिटोरियम, पाथेनिमम गत दिनों छान टू अर्थ ने नेचर सपटेनेबिलिटी रिसर्च संस्थान की एक रपट प्रकाशित की है, जिसमें बहुत दिनों से चिंता का कारण बनी खरपतवार की समस्या पर वैज्ञानिक शोध की

मुहर लगा दी है। इसके मुताबिक हर वर्ष भारत में 15,500 वर्ग किलोमीटर गैर कृषि क्षेत्र आक्रामक खरपतवारों की चपेट में आ रहा है, जिससे 14.40 करोड़ आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इसके साथ कृषि भूमि और वन्यप्राणी आवास भी प्रभावित हो रहे हैं। 27.9 करोड़ पशु, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि के छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं। हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 2022 तक खरपतवारों के आक्रमण से 266,954 वर्ग किलोमीटर पशु चारा क्षेत्र और 212,450 वर्ग किलोमीटर शाकाहारी वन्यप्राणी आवास और 105,725 वर्ग किलोमीटर टाइगर आवास खरपतवारों के कारण अनुत्पादक हो चुके हैं। भारत का 2/3 प्राकृतिक क्षेत्र खरपतवारों की चपेट में आ चुका है, जिससे घुमंतु पशुपालक, घरेलू चरागाह आधारित पशुपालक और वन्यप्राणियों के लिए ज़रूरी घास चारा प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। इन संसाधनों पर निर्भर समुदाय आजीविका के संकट में आ गए हैं और कई बार विस्थापन के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक आकलन के अनुसार 1960 से 2020 तक 8 लाख,30 हजार करोड़ की हानि अर्थव्यवस्था को पहुंची

है। जैव विविधता का जो विनाश खरपतवारों के कारण हुआ है, उसके कई प्रत्यक्ष प्रकृसान के अलावा अप्रत्यक्ष भी की हानि हुई है। वन्यप्राणी और मानव संघर्ष के बढ़ने से जनधन की हानि हो रही है। खासकर किसान ही इसका डक डोल रहे हैं। हाथी, बंदर, सुअर,नीलगाय, और मांसाहारी शेर-चीता आदि भी वनों में भोजन न मिलने के कारण गिर वा या खेतों की ओर मुंह कर रहे हैं। एक ओर वन क्षेत्र घट रहा है, दूसरी ओर बचा हुआ अनुत्पादक होता जा रहा है।

हिमालय क्षेत्र पहले ही आजीविका कमाने की दृष्टि से संघर्ष पूर्ण क्षेत्र है, वहां स्थिति ज्यादा खराब है। यहां खेती और पशुपालन पर निर्भरता भी 90 प्रतिशत के आसपास है। वन्यप्राणी-मानव संघर्ष के चलते बहुत से क्षेत्रों में किसान अपनी जमीन खाली छोड़ने पर विवश हो चुके हैं। इसके अलावा ईंधन आपूर्ति और स्थानीय उपयोग के लिए विविध दस्तकारी के लिए कच्चा माल देने वाले उत्पाद और दवा-दूरी के लिए जड़ी-बूटी के न मिलने के कारण आजीविका के लिए स्थितियां कठिन तर होती जा रही हैं। हेरानी का विषय है कि आज तक इस समस्या को चिह्नित ही नहीं किया गया है। इसीलिए इसके समाधान के लिए

कोई संस्थागत व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। यह अब प्रशासन और विज्ञान जगत के लिए एक चुनौती है कि वे किस कुशलता से इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हैं और इसके निराकरण के लिए मिशन मोड में प्रयास शुरू करते हैं।

किसी प्राकृतिक संसाधन का इस तरह विनष्ट हो जाना राष्ट्रीय हानि है, जिसकी भरपाई समय पर न संभले तो करना कठिन हो जाएगी। हम हिमाचल प्रदेश में मनरेगा जैसे प्रावधानों को इस कार्य में प्रयोग करने का आग्रह सरकार से करते रहें हैं। आशा है इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा और केंद्र सरकार को इस कार्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि राज्य सरकारों के पास खास कर हिमाचल प्रदेश-उतराखंड जैसे राज्य जो अपना खर्च कर्ज लेकर चलाने को मजबूर हैं उनके लिए एक नया बोझ समुद्री आसान नहीं है। किन्तु केंद्र सरकार तो मनरेगा में भी बजट कम करती जा रही है। केंद्र सरकार यदि राज्यो को इस काम के लिए विशेष कार्य-संबद्ध सहायता दे तो कार्य की शुरुआत हो सकती है, वरना लगातार वन-चारागाह क्षेत्र अनुत्पादक होते रहेंगे और देश और किसानों की आर्थिकी पर दुष्प्रभाव बढ़ता जाएगा।

आदिवासी महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व

- **सावित्री ठाकुर**

भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन-पद्धतियों वाला समृद्ध देश है, और इसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ से अधिक है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। यह केवल जनसंख्या का आँकड़ा नहीं, बल्कि भारत की जीवंत, प्राचीन और बहुविध सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय स्वरूप है। यह समुदाय न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संवाहक रहा है, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, भाषा-भाषाई विविधता और मौलिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक पहचान को निर्मित करता रहा है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता और प्रकृति से गहरे संबंध का उल्लेख मिलता है। फिर भी, लंबे समय तक आदिवासी समाज को मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया। उन्हें एक जीवित संस्कृति के संरक्षक के रूप में तो देखा गया, पर समान भागीदार के रूप में नहीं। विविधता आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व, कौशल, सामाजिक समझ और समुदाय निर्माण में उनकी भूमिका को लंबे समय तक वह मान्यता नहीं मिली, जिसकी वे वास्तविक हकदार थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में इस सोच और व्यवस्था में स्पष्ट था उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार ने टोकनिज्म (प्रतीकात्मक पहल) से आगे बढ़कर टार्गेटेड एम्पावरमेंट (लक्ष्य

आधारित सशक्तिकरण) की नीति अपनाई है। जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा में अब कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र इसी समावेशी दृष्टि का सशक्त उदाहरण बन चुका है। इसी प्रतिबद्धता का प्रभाव बजट आवंटन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनजातीय समुदायों के विकास हेतु कुल बजट 2024-25 में 10,237.33 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ हो गया है, जो 45.79% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यदि दीर्घकालीन दृष्टि से देखें, तो 2014-15 में ₹4,497.96 करोड़ के बजट के मुकाबले यह राशि पहले 2021-22 में 7,411 करोड़ तक पहुँची और अब वृद्धि 231.83व तक पहुँच गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बड़े हुए आवंटन से स्पष्ट है कि अब आदिवासी समुदाय, खासकर महिलाएँ, विकास की यात्रा में केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। भारत की आदिवासी महिलाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की धुरी रही हैं। वे जल, जंगल और जमीन से जुड़ी पारंपरिक जीवन व्यवस्थाओं की संरक्षक हैं और सामुदायिक निर्णय, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज यह भूमिका केवल पारिवारिक और सामुदायिक स्तर तक सीमित

नहीं रह गई है, बल्कि शासन व्यवस्था से लेकर नीति निर्माण तक दिखाई दे रही है। इस परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली प्रतीक यह है कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं। सरकार ने आदिवासी महिलाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान एवं उनके नेतृत्व को संस्थागत आधार प्रदान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे विकास केवल सुविधाओं का विस्तार न होकर, सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करे।इनमें आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए 2 लाख तक का ऋण मात्र 4% व्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे हस्तशिल्प, कृषि-आधारित कार्य, बांस उत्पाद, पशुपालन, प्रसंस्करण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकसित कर रही हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरु किया गया प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचा रहा है।यह अभियान 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 75 PVTG समुदायों के इन इलाकों में विकास सुनिश्चित कर रहा है, जो लंबे समय से मुख्यधारा से दूर रहे हैं। लगभग 24,104 करोड़ के निवेश के साथ PM- JANMAN आवास, स्वच्छ

जल, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, शिक्षा, सड़क संपर्क और सतत आजीविका जैसे क्षेत्रों में समग्र सुधार ला रहा है। इसके अतिरिक्त, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे उनके कौशल विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही, छत्रवृत्ति योजनाओं ने विशेषरूप से बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। DAY-NRLM ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता, सामूहिक उत्पादन, विपणन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया है।वहीं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर और मातृ-स्वास्थ्य संकेतकों को सुधारने का कार्य किया हैं। पेसा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से पाँचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासी समुदायों को ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की शक्ति दी गई है। इस कानून ने पंचायत और ग्राम सभा में महिला भागीदारी को संरचनात्मक स्तर पर सुनिश्चित किया है, जिसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है। इस अभियान के तहत 20 लाख से अधिक

परिवर्तनकारी प्रतिनिधियों , जिनमें महिला स्वयं-सहायता समूहों की सदस्याएँ, युवा और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं, को शासन, सेवा वितरण और सामुदायिक सशक्तिकरण में स्थानीय नेतृत्व के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। अभियान का लक्ष्य 1 लाख जनजातीय गाँव- विजन 2030 के माध्यम से सहभागी शासन प्रणाली को मजबूत करना है, जिसमें महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित की गई है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अभियान की सराहना की है और कहा है कि जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व ही ‘विकसितभारत@2047’ की आधारशिला है। आज अनेक जनजातीय बहुल गाँवों में महिलाएँ ग्राम संस्थाओं की अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रही हैं, स्वयं-सहायता समूहों कासंचालन कर रही हैं, शासन प्रयोगशालाओं में परिवर्तनकारी नेतृत्व निभा रही हैं और अपने समुदाय को आजीविका एवं विकास योजनाओं से जोड़ रही हैं। साथ ही, वर्ष 2024 में शुरू ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 63,000 से अधिक जन जातीय बहुल गाँवों में समग्र विकास के लिए ₹79,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका एक मुख्य आधार ग्राम समितियों में महिलाओं की प्रत्यक्ष नेतृत्व भूमिका को मजबूत करना है। भारत की विकास यात्रा में आदिवासी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि वे अब केवल सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बन रही हैं। अब हमारा ध्यान

इस बात पर है कि जमीनी स्तर पर उनके नेतृत्व को कैसे और मजबूत बनाया जाए।इसी उद्देश्य से स्थानीय समुदायों में महिला नेतृत्व प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक महिलाएँ प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। वन आधारित आजीविका और हस्त-उद्यमों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में है, जिससे उनके कार्य का मूल्य और सम्मान दोनों बढ़ें। स्वयं सहायता समूहों और आजीविका समूहों के माध्यम से महिलाएँ समाज में सकारात्मक परिवर्तन की सशक्त वाहक बन रही हैं।इस दिशा में डिजिटल साक्षरता और वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण को और व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही, आदिवासी बालिकाओं की उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य के नेतृत्व पदों तक आगे बढ़ सकें।हमारा उद्देश्य स्पष्ट है-आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक संवेदना का विषय नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विस्तार, सतत विकास और समावेशी प्रगति की सबसे मजबूत नींव है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार)

बजट 2026-27: निवेश-प्रेरित वृद्धि के लिए सीआईआई ने सुधारों का प्रस्ताव रखा

एजेंसी नई दिल्ली।भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आगामी आम बजट 2026-27 के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और विदेशी निवेशों को शामिल करते हुए सतत निवेश वृद्धि को बढ़ावा देना और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की गति को बनाए रखना है। सीआईआई ने सुझाव दिया कि वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्रीय पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत और राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत व्यय सहायता में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाए, इसके अलावा 2026-32 के लिए 150 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाहंप्लाह्न (एनआईपी) 2.0 शुरू की जाए, जिन कंपनियों ने महत्वपूर्ण नए निवेश, उत्पादन या कर योगदान के महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए हैं, उन्हें अतिरिक्त कर रियायतें या अनुपालन में छील दी जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि त्वरित मूल्यह्रास लाभ को पुनः लागू किया जाए ताकि नए पूंजीगत व्यय और तकनीकी उन्नयन को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके, विशेषकर लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और विनिर्माण उद्योगों के लिए, बशर्ते कि यह उपाय ऐसा हो कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिले लेकिन न्यूनतम वैकल्पिक कर की देयता उत्पन्न न हो। इसके अलावा, सीआईआई ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) को मजबूत करने का सुझाव दिया और इसके लिए एक संप्रभु निवेश रणनीति परिषद (एसआईएफसी) के गठन की भी सिफारिश की, ताकि निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो सके।

ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवहार में बदलाव आवश्यक: राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए हर नागरिक में व्यवहारिक परिवर्तन बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। यही विचार ‘लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट - लाइफ’ के माध्यम से पूरी दुनिया को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सफलता के लिए हर क्षेत्र और हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए व्यवहार में बदलाव बेहद जरूरी है।

‘राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण सबसे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऊर्जा का बुद्धिमानी से, जिम्मेदारी से और कुशलता से उपयोग करना है। उन्होंने कहा, ‘जब हम अनावश्यक विद्युत उपकरणों के उपयोग से बचते हैं, ऊर्जा-कुशल उपकरण अपनाने हैं, घरों और कार्यस्थलों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं या सौर और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प अपनाने हैं, तो हम न केवल ऊर्जा बचाते हैं बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं।’

आरबीआई ने बैंकों को एमएसएमई ऋण को बाहरी मानक से जोड़ने की सलाह दी: सरकार

नई दिल्ली। मौद्रिक नीति के संचरण में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों को एक बाहरी मानक से जोड़ने की सलाह दी है। सरकार ने संसद को यह जानकारी दी है।

बाहरी मानक प्रणाली के तहत ऋणों के पुनःनिर्धारण की अवधि को तीन महीने कर दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करंडलाजे ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा उधारकर्ताओं को बाहरी मानक आधारित ब्याज दर का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों को परस्पर सहमति से परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले के विभाग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से गुणवत्ता निर्माण आदेश लागू करती है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए छूट और राहत शामिल होती है, ताकि इन आदेशों से घरेलू उत्पादन बाधित न हो।

ईडी का 2026 की शुरुआत तक पुराने फेरा मामलों को निपटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईंडी) ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के तहत दर्ज मामलों को निपटाने का फैसला किया है। यह कानून 25 साल से अधिक पहले 1998 में खस कर दिया गया था। वर्ष 1973 के आपराधिक प्रावधानों से युक्त फेरा कानून की जगह जून 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) ने लिया, जो एक दीवानी कानून है। अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने ऐसे करीब 400-500 मामलों की पहचान की है, जिनमें फेरा के तहत विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटारा जा सकता है। इन मामलों में आरोपी व्यक्ति की या तो मृत्यु हो चुकी है, या उनका कोई पता नहीं है, जिन संपत्तियों को लेकर स्वालत हो, वे नीलाम हो चुकी हैं या अब हैं ही नहीं। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया को आगे कुछ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2026 की पहली तिमाही तक यह काम पूरा हो सकता है। फेरा के तहत अखिरी कारण बताओ नोटिस मई 2002 में जारी किए गए थे।

बढ़ते बकाए के बीच जयपुर डिस्कॉम ने राजस्व वसूली तेज की

एजेंसी जयपुर। राजस्थान की बिजली वितरण कर्पणियों (डिस्कॉम) के सामने बढ़ते बकाए और लंबे समय से चली आ रही ढांचागत चुनौतियों के मद्देनजर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने राजस्व वसूली तेज की है। साथ ही सतर्कता भी बढ़ाई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजस्थान में बिजली वितरण का काम तीन सरकारी डिस्कॉम - जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) करती है। ये राज्य



भारी तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान, बिजली चोरी और बिलों के देरी से भुगतान से जूझ रही हैं जिससे उनके वित्तीय खातों पर लगातार दबाव बना हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजस्व संग्रहण में सुधार और नुकसान को कम

करना डिस्कॉम की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।नवीनतम अधिधान के तहत जयपुर डिस्कॉम ने सबसे ज्यादा बकाया वाले 10 बिजली खंड और 20 उपखंड को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वसूली रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा ने कहा कि इनकी नियमित निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। उन्होंने चिन्हित किए गए उपखंड के सहायक अभियंताओं के साथ वसूली योजना की समीक्षा की है। इसमें कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी शामिल हुए।

डोगरा ने कहा कि चिन्हित 20 उपखंड में 1.11 लाख से ज्यादा

पारेषण प्रणालियां अभी चालू नहीं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक उपलब्ध पारेषण मॉर्जिन के खस हो जाने के कारण इन संयंत्रों से दिन के समय बिजली उत्पादन समय पूरी तरह रोक दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर (एनआरएलडीसी) के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लगभग 23 गीगावाॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता चालू है, जबकि पारेषण क्षमता करीब 18.9 गीगावाॉट है।यह पूरी पारेषण क्षमता दीर्घकालिक सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) वाली परियोजनाओं को आवंटित की जा चुकी है, जिससे टी-जीएनए के तहत संचालित चार गीगावाॉट से

बीएमडब्ल्यू ‘मिनी’ ब्रांड को और मजबूत करेगी, नए मॉडल लाने, बिक्री बढ़ाने पर जोर

एजेंसी नई दिल्ली। जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता बीएमडब्ल्यू अगले साल भारत में अपने ‘मिनी’ पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि मेट्रो शहरों से बाहर बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ हर्दोर्ग सिंह बरार ने यह जानकारी दी।

कंपनी के पोर्टफोलियो में फिलहाल मिनी कूपर, मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू और मिनी कन्वर्टिबल शामिल हैं। ब्रांड को बड़े शहरों से आगे स्वीकृति मिलने के साथ कंपनी छोटे शहरों और कस्बों में अपने बिक्री नेटवर्क का विस्तार करने पर भी ध्यान दे रही है। बरार ने बातचीत

में कहा, ‘हम अगले साल मिनी बिक्री नेटवर्क का और विस्तार पोर्टफोलियो के तहत एक-दो और



उत्पाद लाने पर विचार कर रहे हैं। ‘ बीएमडब्ल्यू अगले साल अपने

बिक्री नेटवर्क का और विस्तार पोर्टफोलियो के तहत एक-दो और



रॉंची जैसे स्थान शामिल होंगे। साथ ही ऐसे छोटे शहर भी होंगे जहां कंपनी

सर्सीफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की घटी कीमत

एजेंसी मुंबई। घरेलू सर्सीफा बाजार में आज मामूली गिरावट नजर आ रही है। कीमतों में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्सीफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,33,900 रुपये से लेकर 1,34,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,22,740 रुपये से लेकर 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्सीफा बाजार में आज 1,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,34,060 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,22,740 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,22,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,22,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के

स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्सीफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,34,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,22,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,34,060 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,22,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्सीफा बाजार में भी आज सोने के भाव में मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दो साल में योनो ऐप के उपयोगकर्ताओं को दोगुना कर 20 करोड़ करने का लक्ष्य: एसबीआई चेयरमैन

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस सेठी ने कहा कि बैंक सोमवार को योनो ऐप का नया संस्करण पेश करने के साथ अगले दो वर्षों में इसके उपयोगकर्ता आधार को दोगुना कर 20 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

उन्होंने दिए एक साक्षात्कार में बताया कि ‘योनो 2.0’ एक बड़ा अपग्रेड है, जो ग्राहकों को बेहतर अनुभव देगा और बैंक के लिए एक मजबूत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसकी सभी विशेषताएं 6-8 महीनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘बैंक के नजरिए से योनो 2.0 डिजिटलीकरण का एक अहम आधार है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक समान कोड है। इससे सभी



अपनी डिजिटल मौजूदगी और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए करना चाहता है।’ उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योनो 2.0 में खाता खोलने या किसी भी अन्य लेनदेन के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और शाखा चैनलों पर एक समान और निर्बाध

अनुभव सुनिश्चित होगा।

एसबीआई चेयरमैन ने कहा, ‘आज हमारे पास लगभग 10 करोड़ ग्राहक आधार है और हमारा उद्देश्य

में हमारे पास कम से कम 20 करोड़ का ग्राहक आधार हो।’

सेठी ने दिसंबर की मौद्रिक नीति में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बावजूद तीन प्रतिशत शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर भरोसा जताया।दर कटौती के बाद एसबीआई ने भी रेपो से जुड़ी अपनी ऋण दर में 0.25 प्रतिशत की कमी कर इसे 15 दिसंबर से 7.90 प्रतिशत कर दिया। बैंक ने सभी अवधियों के लिए सीमांत लागत-आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में भी 0.5 प्रतिशत की कटौती की है।एसबीआई चेयरमैन ने यह भी कहा कि बैंक को अगले 5-6 वर्षों में ऋण वृद्धि को आगे बढ़ाने और 15 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए इक्विटी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर: रिपोर्ट

एजेंसी नई दिल्ली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ‘ग्लोबल एआई वाइब्रेंसीटी’ की हालिया रिपोर्ट में भारत ने कृत्रिम मेधा (एआई) में विश्व की प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। ‘ग्लोबल एआई वाइब्रेंसीटी टूल’ शोध एवं विकास, प्रतिभा, अवसंरचना सहित सात प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का आकलन करता है।

नवंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने चार स्थान की छलांग लगाई है और कृत्रिम मेधा में प्रतिस्पर्धी क्षमता के मामले में ब्रिटेन के साथ-साथ एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2024 के ‘ग्लोबल

वाइब्रेंसी’ सूचकांक में भारत 21.59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।



इसके बाद दक्षिण कोरिया (17.24 अंक) और ब्रिटेन (16.64 अंक) का स्थान है। भारत 2023 में सातवें स्थान पर था जबकि ब्रिटेन छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों ने वैश्विक

आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य: आरबीआई रिपोर्ट

एजेंसी विजयवाड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में देश का नंबर एक राज्य बनकर उभरा है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश ने देश में फल उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने 1.93 करोड़ टन फलों का उत्पादन करके देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश ने मछली उत्पादन में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां राज्य ने 51.58 लाख टन मछली का उत्पादन किया। आंध्र प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य उत्पाद (जीएसडीपी) 15.93 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2.66 लाख रुपये है और बिजली उपलब्धता के मामले में आंध्र प्रदेश देश में 1481 यूनिट के साथ 14वें स्थान पर है। जनसंख्या स्वास्थ्य के मामले में, आंध्र प्रदेश में औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष दर्ज की गई है। पुरुषों के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष और महिलाओं के लिए 73 वर्ष है।



कंपनियां उच्च लाभ वाले एआई चिप पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिससे टीवी जैसे पारंपरिक उपकरणों के लिए आपूर्ति कम हो रही है। हार्पर अत्यायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एन एस सतीश ने बताया कि मेमोरी चिप की कमी और कमजोर रुपये के

मेमोरी चिप की कमी, कमजोर रुपये के कारण जनवरी से टीवी हो सकते हैं महंगे

कई वैश्विक ब्रांडों के लाइसेंस रखने वाली टीवी विनिर्माता कंपनी सुपर प्लास्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल) ने कहा, ‘पिछले तीन महीनों में मेमोरी चिप की कीमतों में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’ एसपीपीएल के मुख्य कार्यपालक



कारण एलईडी टीवी सेटों की कीमतों में तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी।कुछ टीवी विनिर्माताओं ने कीमतों में संभावित वृद्धि के बारे में अपने डीलरों को पहले ही सूचित कर दिया है। थॉमसन, कोडक और ब्लाउंकुट सहित

अधिकारी (सीईओ) अवनीत सिंह

मादवाह के अनुसार, मेमोरी चिप संकट

और रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव के

कारण जनवरी से टेलीविजन की कीमतों में सात से 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

महंगाई के आकड़े, विदेशी निवेशकों का रुख, वैश्विक रुझान तय करेंगे शेयर बाजार की दिशा: विश्लेषक

एजेंसी नई दिल्ली। विश्लेषकों ने कहा कि इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई के आंकड़े, विदेशी निवेशकों के रुख और वैश्विक संकेतों से तय होगी। इसके अलावा, निवेशकों की नजर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी रहेगी। बाजारों में पिछले सप्ताह उतार-चढ़ाव रहा और वे नकारात्मक दायरे में बंद हुए। बीते सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 444.71 अंक यानी 0.51 प्रतिशत गिरा। रेलिंगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, ‘इस सप्ताह घरेलू स्तर पर कई आंकड़े आने हैं, जिसमें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई और व्यापार संतुलन के आंकड़े प्रमुख हैं। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं से जुड़े घटनाक्रम पर भी नजर रहेगी। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन और वहां से आने वाले व्यापक आर्थिक संकेत निकट अवधि में निवेशकों की भावना को प्रभावित करेंगे।’

इस महीने के पहले दो हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 17,955 करोड़ रुपये निकाले हैं, जिससे 2025 में अब तक कुल निकासी बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है। मिश्रा ने कहा कि विदेशी कोषों की लगातार निकासी और रुपये में तेज गिरावट ने निवेशकों के भरोसे पर भारी दबाव डाला है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने संपत्ति प्रबंधन के शोध प्रमुख सिद्धार्थ खेनका ने कहा, ‘कुल मिलाकर हमें उम्मीद है कि बाजार सीमित दायरे में रहेगे, हालांकि व्यापक सूचकांकों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कोई ठोस प्रगति होती है तो इससे बाजार में एक सार्थक तेजी आ सकती है।’

हैदराबाद में परिचालन के पहले वर्ष में गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 2,600 करोड़ रुपये से अधिक के घर बेचे

एजेंसी मुंबई। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में परिचालन के पहले वर्ष में 2,600 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियां बेची हैं। रियल एस्टेट कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कंपनी इस शहर में कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है, जहां विकास के

अपार अवसर हैं। इस साल जनवरी ने हैदराबाद के बाजार में बेहद अच्छ प्रदर्शन किया है। पिरोजशा ने कहा, ‘हमने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान हैदराबाद में अपनी पहली परियोजना शुरू की है। हमने जुलाई-सितंबर तिमाही में अपनी दूसरी परियोजना शुरू की। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से हमने शहर में अपने परिचालन के पहले वर्ष में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री बुकिंग हासिल की है।’ उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाजार में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं और कंपनी प्रीमियम और लक्जरी आवासीय संपत्तियों की मजबूत मांग का लाभ उठाने के लिए इस शहर में अपना कारोबार बढ़ाना चाहेगी।

घरेलू तांबा उद्योग ने सस्ते आयात पर जताई चिंता, तीन प्रतिशत सुरक्षा शुल्क की मांग

एजेंसी नई दिल्ली। उद्योग निकाय आईपीसीपीए ने कहा कि कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत तांबे के सस्ते आयात से भारतीय विनिर्माण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही उसने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षा

शुल्क लगाने और विदेशों से आने वाले आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने की मांग की है। इंडियन प्राइमरी कॉपर व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत तांबे के सस्ते आयात से भारतीय विनिर्माण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही उसने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षा

20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।आईपीसीपीए ने कहा, ‘एफटीए साझेदारों से शु्र्य शुल्क पर हो रहे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीसीपीए) के अनुसार, शु्र्य शुल्क पर तांबे के आयात के चलते देश के घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, जबकि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हाल के वर्षों में

कोलंबो बंदरगाह पर समुद्र में 200 लीटर से ज्यादा कच्चे तेल का रिसाव

कोलंबो। श्रीलंका के सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि कोलंबो बंदरगाह पर पाइपलाइन में रिसाव होने के कारण 200 लीटर से अधिक कच्चा तेल समुद्र में फैल गया। कंपनी के अनुसार, यह लीक कोलंबो बंदरगाह के पास ईंधन टैंकर से कच्चा तेल उतारने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइपलाइन में पाया गया। प्रभावित पाइपलाइन से ईंधन उतारने का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है तथा रिसाव और अधिक तेल फैलाव को रोकने के लिए मरम्मत जारी है। इस बीच श्रीलंका तटरक्षक बल ने समुद्री पानी में मिल चुके कच्चे तेल को हटाने का अभियान शुरू किया है और प्रभावित क्षेत्रों में सफाई कार्यों को अंजाम देने के लिए एक जहाज की तैनाती की है।श्रीलंका नौसेना भी लीक रोकने और बहाली के प्रयासों में तटरक्षक बल की मदद कर रही है। समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने बताया कि कच्चे तेल के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिये गये हैं। हाल के वर्षों में इन पाइपलाइनों में कई बार तेल का रिसाव हो चुका है।

ईरान में घुसने की कोशिश करने वाले 398 लोगों को अफगानिस्तान सेना ने किया गिरफ्तार

काबुल। अफगानिस्तान सेना ने पिछले सप्ताह सीमा पर कर ईरान में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले 398 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पश्चिमी क्षेत्र की सेना यूनिट ने बताया कि ये लोग पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से सीमा पार कर पड़ोसी देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रारंभिक जांच के बाद सभी को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पिछले महीने भी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में अवैध रूप से ईरान में प्रवेश के प्रयास में करीब 400 व्यक्तियों की गिरफ्तारी का सूचना दी थी।यह भी सच है कि हर दिन सैकड़ों अफगान शरणार्थी ईरान से अपने देश अफगानिस्तान लौटते हैं, लेकिन युद्ध के बाद गरीबी और बेरोजगारी से बचने के लिए हर दिन कई अफगान अवैध रूप से ईरान चले जाते हैं। अफगानिस्तान सरकार ने मानव तस्करी और पड़ोसी देशों में अवैध रूप से सीमा पार करने पर रोक लगाने का वादा किया है।

15 को संयुक्त राष्ट्र पहला विश्व तुर्की भाषा परिवार दिवस मनाएगा

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने समरकंद की आम सभा में 15 दिसंबर को हर साल विश्व तुर्की भाषा परिवार दिवस मनाने का फैसला लिया है। यह समारोह तुर्की भाषा बोलने वाले लोगों की साझा भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है और बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के प्रति यूनेस्को की व्यापक प्रतिबद्धता को दृढ़ करता है। तुर्की भाषा परिवार में अजरबैजानी, कजाख, किर्गिज, तुर्की, तुर्कमेन, उज्बेक जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। इसे करीब एक करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में 20 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। इसलिए सोमवार को पहली बार इसे मनाने की तैयारी में संगठन जुटा है। यूनेस्को का मानना ​​है कि इन भाषाओं में एक समृद्ध लिखित विरासत, मजबूत मौखिक परंपराएं और कई सदस्य देशों में फैली विविध सांस्कृतिक प्रथाएं सन्निहित हैं। तुर्की भाषा दिवस की घोषणा अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किये और उज्बेकिस्तान के संयुक्त अनुरोध के बाद की गई है। इसे 21 सदस्य देशों का समर्थन मिला। इसे मनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे भाषा विज्ञान के इतिहास का खास दिन होना है। इसी दिन 1893 में डेनिस भाषाविद विल्हेम थॉमसन ने घोषणा की थी कि उन्होंने ओरखोन शिलालेखों की वर्णमाला को समझ लिया है, जो तुर्की भाषा परिवार के सबसे पुराने ज्ञात लिखित रिकॉर्ड में से एक है। उनकी इस खोज ने एक ऐसी भाषाई परंपरा को गहराई से समझने का रास्ता खोला, जो आज यूरेशिया के दर्जनों समुदायों को आपस में जोड़ती है।

नोबेल पुरस्कार विजेता अलेस बियाल्यात्सकी की रिहाई का मानवाधिकार संगठनों ने किया स्वागत

स्टॉकहोम। कई मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेस बियाल्यात्सकी की रिहाई का स्वागत किया है। मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था राइट लाइवलीहुड ने उनकी रिहाई का स्वागत करते हुए इसे 'न्याय की दिशा में बहुत देर से आया कदम' बताया है। संस्था ने कहा कि जुलाई 2021 में उनकी कैद अवैध और राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। संस्था ने जोर दिया, 'हम वि्यासना की सदस्य मारफा राबकोवा और बेलारूस में अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के कारण कैद किये गये सभी अन्य लोगों की तत्काल रिहाई की अपनी आपात अपील को फिर से दोहराते हैं।' उल्लेखनीय है कि वियासना मानवाधिकार केंद्र की स्थापना श्री बियाल्यात्सकी ने की थी।। श्री बियाल्यात्सकी की सात विवासनो के उनके दो अन्य दो सहयोगियों को भी रिहा किया गया है। गौरतलब है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के 2020 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे।

यूक्रेन का आरोप– रूसी ड्रोन हमले में तुर्किये का नागरिक जहाज बना निशाना

एजेंसी कीव। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस ने एक ड्रोन हमले के जरिए तुर्किये के एक नागरिक जहाज को जानबूझकर निशाना बनाया। यह जहाज सनपतावर ऑयल लेकर मिश्र जा रहा था। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के दो बंदरगाहों पर भी हमले किए थे।यूक्रेनी नौसेना ने टेलीग्राम पर जारी बयान में बताया कि प्रभावित जहाज का नाम ‘वीवा’ है, जिस पर 11 तुर्किये नागरिक सवार थे। नौसेना के अनुसार, हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और जहाज सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रखते हुए मिश्र की ओर बढ़ रहा है।बयान में कहा गया कि यह हमला खुले समुद्र में यूक्रेन के विशेष



आर्थिक क्षेत्र में किया गया, जो यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमा से बाहर है। यूक्रेन ने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताते हुए

रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नौसेना ने यह भी स्पष्ट किया कि वह

जहाज के कप्तान के संपर्क में है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।इससे पहले, 12 दिसंबर को रूस द्वारा किए गए हमलों में यूक्रेन के दो

बुजुर्ग भी शामिल था।हमले की जांच कर रही टीम ने बताया कि दोनों शूटर्स ने हमले को अंजाम देने से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि वे मछली पकड़ने के लिए साउथ कोस्ट जा रहे हैं। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक मास शूटिंग बताया जा रहा है। का बेटा यह है कि फायरिंग की घटना एक ऐसे देश में हुई है, जो बंदूकों पर नियंत्रण के लिए बनाए अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। अधिकारियों ने कहा कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में

बंदरगाहों को निशाना बनाया गया था, जिसमें तुर्किये के स्वामित्व वाले तीन जहाज क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन हमलों के दौरान एक जहाज में भीषण आग लगने की खबर भी सामने आई थी। यूक्रेन का कहना है कि ये घटनाएं उस चेतावनी के बाद हुई हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन को समुद्री मार्गों से ‘पुरी तरह अलग’ करने की धमकी दी थी। यह चेतावनी तब दी गई थी, जब यूक्रेन ने रूस से तेल निर्यात के लिए जा रहे तथ्यांकवित ‘शैडो फ्लीट’ के तीन टैंकरों को नुकसान पहुंचाया था। काला सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।

एजेंसी अबू धाबी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एच.एच. शेख अब्दुल्ला बिन जयद अल नाहयान से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। श्री जयशंकर श्री जायद अल नाहयान के साथ 16वीं भारत-यूईई संयुक्त आयोग और 5वीं रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अबू धाबी में अपने कार्यक्रमों के बाद, विदेश मंत्री भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग का

विस्तार करने के उद्देश्य से इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सर के साथ बातचीत करने के लिए इजरायल जाएंगे।यह यात्रा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के बाद हो रही है। बातचीत के दौरान श्री मोदी और श्री नेतन्याहू ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में जारी गति

पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी थी। उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, शून्य-विचारों को खारिज करने का आह्वांन किया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्वीय प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की थी।

चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए जोस एंटोनियो कास्ट

ऑस्ट्रेलिया : सिडनी गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई

एजेंसी सैंटियागो । जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बन गए हैं।

चुनाव अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कास्ट ने राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। चिली चुनाव आयोग के अनुसार रन-ऑफ में 99.33 फीसदी वोटों की गिनती हुई। कास्ट को 99.33 में से 58.18 फीसदी वोट मिले। वहीं चिली के सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार जीनेट जारा को 41.82 फीसदी वोट मिले। जारा ने सोशल मीडिया पर कास्ट से हर मान ली और उन्हें बधाई दी। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि मीजूला राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने भी उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। अपनी जीत के बाद, कास्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

एक्स पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया, ‘धन्यवाद, चिली! अब काम पर लगने का समय है!’ बता दें, कास्ट लंबे समय से दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनते आ रहे हैं। इस चुनाव में अपराध सबसे अहम मुद्दा रहा। कास्ट की उम्र 59 साल है



और वह 11 मार्च, 2026 को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 16 नवंबर को पहले राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50 फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले। इसका मतलब

था कि जारा और कास्ट रन-ऑफ के लिए आगे बढ़ गए। पहले चरण में जारा को 26.85 फीसदी और कास्ट को 23.92 फीसदी वोट मिले थे।

चिली के कानून के तहत, अगर चुनाव के पहले राउंड में किसी को भी आधे से ज्यादा वोट नहीं मिलते,

तो दोनों आगे चल रहे उम्मीदवार को रन-ऑफ के लिए जाना पड़ता। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने अपने भाषण में जारा और कास्ट को बधाई दी। बोरिक ने घोषणा की थी, ‘14

दिसंबर को चिली एक बार फिर हमारे देश के राष्ट्रपति को चुनेगा, जो अपने चार सालों के लिए हमारे देश की किस्मत तय करेंगे। मुझे यकीन है कि चिली के लिए बातचीत, सम्मान और प्यार किसी भी मतभेद से पहले आएगा।’ स्थानीय समयानुसार रन-ऑफ में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे खत्म हुई, जिसमें 15 मिलियन से ज्यादा पंजीकृत वोटर थे। वोटिंग के दौरान कास्ट सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे। अपराध को लेकर उनके सख्त तैवर लोगों को पसंद आए। इसके साथ ही लोगों में लोकप्रियता की वजह उनकी गैरकानूनी तरीके से आए प्रवासियों को लेकर उनकी सोच भी है। वामपंथी शासन के दौरान बढ़ते अपराध के मामलों से लोग काफी परेशान हो चुके थे। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी बदलाव के लिए वोट करेंगे।

राष्ट्रपति पौडेल ने अंतरिम सरकार से संसदीय चुनाव पर पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहा



एजेंसी काठमांडू। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम सरकार को प्रतिनिधि सभा के लिए तय की गई 05 मार्च की चुनाव तिथि पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने यह सुझाव दिया। उनके प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने बताया कि राष्ट्रपति पौडेल ने सरकार को चुनाव प्रभावित न करने वाले सभी कार्य करने की भी सलाह दी है। राष्ट्रपति ने पहले की तुलना में कहीं अधिक सतर्कता और तत्परता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश नेपाली सेना सहित सभी सुरक्षा निकायों को दिए राष्ट्रपति पौडेल ने वर्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न हो चुकी तथा भविष्य में सामने आ सकने वाली सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारियों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का विश्वास भी व्यक्त किया।

नेपाल निर्वाचन आयोग नेआचार संहिता-2082 में नए प्रावधान जोड़े , आय-व्यय बैंकिंग प्रणाली से अनिवार्य

से खर्च करना अनिवार्य होगा। साथ ही, खर्च करने के लिए उम्मीदवार की आय-व्यय बैंकिंग प्रणाली से अनिवार्य

जिम्मेदार पदाधिकारी के माध्यम से ही खर्च करना होगा। इसी तरह, 25 हजार रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता बैंक या वित्तीय संस्था के



का नाम-पता सहित विवरण संबंधित निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना भी जरूरी होगा। प्रस्तावित आचार संहिता में यह भी उल्लेख है कि राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलकर दल द्वारा नियुक्त

माध्यम से ही स्वीकार करनी होगी। किसी व्यक्ति या संस्था से स्वीच्छक सहयोग के रूप में नकद राशि प्राप्त होने पर रसीद या भरपाई जारी कर उसे बैंक या वित्तीय संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। आय-व्यय का पूरा विवरण तथा संबंधित बिल-भरपाई भी सुरक्षित रखनी होगी।

हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और पत्नी की हत्या, बेटा मुख्य संदिग्ध

एजेंसी लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता और अभिनेता रॉब रेनर और उनकी पत्नी, मिशेल सिंगर रेनर, लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। ‘पीपेल’ पत्रिका ने कई सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। टुर्गोस एंजिल्स अभिनयन विभाग ने यह जानकारी दी। दमकलमियों ने रेनर के घर से दो व्यक्तियों के शव मिलने की सूचना दी। टीएमजेड पोर्टल के अनुसार, ‘दोनों पीड़ितों के शरीर पर छुरा घोंपने के निशान मिले हुए गहरे कटे हुये थे। ‘ पत्रिका के सूत्रों के अनुसार, इस हत्या के मामले में दंपति के बेटे निक रेनर मुख्य संदिग्ध हैं, जिसका नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। पुलिस ने फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है लेकिन निक रेनर से पूछताछ की जा रही है। रॉब रेनर ने 1960 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बाद में एक निर्देशक के रूप में प्रभावशाली पहचान बनाई। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में ‘द बकेट लिस्ट’ (2007) और ‘ए फ्यू गुड मेन’ (1992) शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने 2013 में ‘द बुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट’ में मुख्य किरदार के पिता की भूमिका भी निभाई थी। उनकी अन्य समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में ‘स्टैंड बाय मी’, ‘द प्रिंसेस ब्राइड’, ‘क्लेन हैरी मेट सेली...’ और ‘मिजरी’ शामिल हैं।



जयशंकर जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग- रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर करेंगे चर्चा

एजेंसी अबू धाबी। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एच.एच. शेख अब्दुल्ला बिन जयद अल नाहयान से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। श्री जयशंकर श्री जायद अल नाहयान के साथ 16वीं भारत-यूईई संयुक्त आयोग और 5वीं रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अबू धाबी में अपने कार्यक्रमों के बाद, विदेश मंत्री भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग का

विस्तार करने के उद्देश्य से इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सर के साथ बातचीत करने के लिए इजरायल जाएंगे।यह यात्रा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के बाद हो रही है। बातचीत के दौरान श्री मोदी और श्री नेतन्याहू ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में जारी गति



दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के बाद हो रही है। बातचीत के दौरान श्री मोदी और श्री नेतन्याहू ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में जारी गति

सिडनी हमला : शूटर नवीद अकरम ने 2019 में खुफिया एजेंसी को भी दे दिया था गच्चा, 6 साल बाद किया कत्लेआम

एजेंसी सिडनी । ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर पाकिस्तान के रहने वाले थे। जांच के दौरान पता चला कि लाइव के रहने वाले पिता-पुत्र ने हनुवक्का उत्सव मनाने के लिए एकत्र भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें 15 लोग मारे गए। आठ दिवसीय हनुवक्का उत्सव की शुरुआत हुई थी, तभी बोंडी बीच पर मौजूद लोगों पर दो लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। शूटर्स ने न बच्चा देखा और न बूढ़ा, जो सामने पड़ा,

गोलियों से भून दिया। अफरातफरी मचने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और सात हमलावर देर कर दिया गया। मरने वाले की पहचान साजिद अकरम (50) के रूप में हुई। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्यन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जवाबी कार्रवाई में साजिद का बेटा नवीद अकरम (24) घायल हो गया। इस हमले में सबसे कम उम्र की पीड़ित 10 साल की लड़की थी, जिसकी बच्चों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मरने वालों में 87 साल का

बुजुर्ग भी शामिल था।हमले की जांच कर रही टीम ने बताया कि दोनों शूटर्स ने हमले को अंजाम देने से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि वे मछली पकड़ने के लिए साउथ कोस्ट जा रहे हैं। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक मास शूटिंग बताया जा रहा है। का बेटा यह है कि फायरिंग की घटना एक ऐसे देश में हुई है, जो बंदूकों पर नियंत्रण के लिए बनाए अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। अधिकारियों ने कहा कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में

जन्मा नागरिक है। ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क के मुताबिक साफिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसे 2001 में पार्टनर वीजा और बाद में रेंजिडेंट रिटर्न वीजा में बदल दिया गया था। हमले के बाद पुलिस ने रविवार रात साउथ-वेस्ट सिडनी के बोनीरिंग में शूटर्स के घर पर और साथ ही कैम्पसी में एक प्रॉपर्टी पर रेड ड्रावी। पुलिस को बोंडी में कैपेबेल परेड पर एक गाड़ी भी मिली जिसमें कई इम्योवाइज्ड एक्सप्लोसिव ड्रिवाइस

मौजूद थे। कमिश्नर लैन्यन ने कहा, ‘एक रेस्क्यू बम डिपोजलड यूनिट अभी वहां है, जो गाड़ी पर काम कर रही है। ‘ पुलिस अधिकारी ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। कमिश्नर लैन्यन ने कहा कि संदिग्धों के हथियार और कार में विस्फोटक मिले हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रांडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम (जेसीटीटी) की जांच करने वाली टीम में स्टेट और फेडरल दोनों एजेंसियां शामिल हैं। जेसीटीटी का मानना ​​है कि हमलावरों ने इस्लामिक

स्टेट टेररिस्ट ग्रुप के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। सीनियर अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि बोंडी बीच पर हमलावरों की कार के अंदर आईएस के दो झंडे मिले। मौके से मिले फुटज में एक झंडा गाड़ी के बोनट पर लगा हुआ दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि खुफिया एजेंसी एसआईओ की नजर में नवीद अकरम पहली बार अक्टूबर 2019 में आया था। करीब छह महीने तक उसकी जांच की गई, लेकिन वह भी अधिकारियों ने पाया कि उससे कोई

खतरा नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, नवीद अकरम का संबंध आईएस आतंकी मतारी से था। मतारी फिलहाल सात साल की जेल की सजा काट रहा है। उसने खुद को आतंकवादी ग्रुप का ऑस्ट्रेलियाई कमांडर बताया था। मतारी एक आईएस सेल का हिस्सा था। इस सेल में सिडनी के कई और लोग भी शामिल थे, जिन्हें बाद में आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। जांच की करीबी जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि ये लोग नवीद अकरम के भी करीबी थे।

यरुशलम/गाजा। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने गाजा पट्टी में एक हमले में हमास के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास की सैन्य शाखा में हथियार निर्माण मुख्यालय के प्रमुख राद साद को मार दिया गया है। इजरायली सेना के अनुसार, साद सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास द्वारा किये गये योजनाकारों में से एक था और अंतिम बचे हुए शीर्ष सरगनाओं में एक था। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि साद हाल के महीनों में हमास द्वारा ‘संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार’ था। सेना ने यह भी आरोप लगाया कि वह संघर्ष विराम के दौरान हथियारों का निर्माण जारी रखने के लिए भी जिम्मेदार था। इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा बयान में एक बयान में उन्होंने और रक्षा मंत्री इजरायल काउज़ ने शनिवार को गाजा में इजरायली बलों को घायल करने वाले हमास के एक विस्फोटक उपकरण के विस्फोट के जवाब में साद की हत्या का व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था। इससे पहले शनिवार को, इजरायली सेना ने बताया था कि दक्षिणी गाजा में आतंकवाद विरोधी एक अभियान के दौरान साद को मृत फन जने से दो सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए थे।इजरायल के एक पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी माइकल मिल्टस्टीन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, ‘साद को मानना हमास के लिए व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों रूप से एक झटका है।’

पॉलीहाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती

By Bhupender
(Dainik Jagriti)

सब्जी उत्पादन और आधुनिक बागवानी में पॉलीहाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखें तो इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती एक वरदान के रूप में सिद्ध हो सकती है। पॉलीहाउस में आमतौर पर सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है, किन्तु सब्जियों का चयन पौधों की ऊंचाई, मौसम, सब्जी तैयार होने का समय, उत्पादन लागत एवं बाजार भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

इसके लिए ज्यादातर उन सब्जियों को चुनें जो कम जगह घेरती हों और उनका बाजार भाव ज्यादा मिलता हो। पॉलीहाउस में उगाने के लिये निम्न सब्जियां उपयुक्त रहती हैं, जैसे- शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, खरबूजा, लौकी, गोभी, बैंगन, फ्रेंचबीन, करेला, चप्पनकहू और तरबूज आदि प्रमुख हैं।

ढांचे की बनावट के आधार पर पॉलीहाउस कई प्रकार के होते हैं। पॉलीहाउस को बने के लिये बांस की खपच्ची, बांस, जी आई पाइप, आयरन एंगल, सुतली आदि का प्रयोग ढांचा बनाने के लिये किया जाता है और इसे 150 से 200 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन से ढंका जाता है। पॉलीथीन शीट का पराबैंगनी होना जरूरी होता है। सूर्य का प्रकाश पारदर्शी पॉलीथीन से पॉलीहाउस के अन्दर पहुंचता है, किन्तु विकिरण से पुनः वायुमण्डल में प्रवेश न कर पाने के कारण वह पॉलीहाउस का तापमान बढ़ाने में सहायक होता है। किसानों के लिये कम लागत के पॉलीहाउस उपयुक्त होते हैं और विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा इन पर बागवानी मिशन के तहत 50 तक प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

कम लागत के पॉलीहाउस- इस प्रकार के ग्रीन हाउस का ढांचा बांस की खपच्चीयों तथा सुतली की सहायता से बनाया जाता है। इस प्रकार के पॉलीहाउस में कोई भी यंत्र वातावरण का नियंत्रण करने के लिये नहीं लगाया जाता एवं ऐसे पॉलीहाउस मैदानी क्षेत्रों के लिये सर्दी की ऋतु में प्रयोग किये जा सकते हैं।

मध्यम लागत के पॉलीहाउस- इस प्रकार के ग्रीन हाउस का ढांचा प्रायः लोहे के पाइप या जी आई पाइप द्वारा बनाया जाता है। इसमें कुत्तर, छाया देने वाले जाल, पानी के फव्वारे तथा गर्म हवा फेंकने वाले ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। इस में वातावरण को अर्धनियंत्रित किया जा सकता है।

अधिक लागत के आधुनिक पॉलीहाउस- ये ग्रीन हाउस मध्यम लागत वाले पॉलीहाउस से काफी बड़े आकार के होते हैं। इसमें वातावरण का नियंत्रण आधुनिक यंत्रों द्वारा किया जाता है, जिसको कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता है और सिंचाई ड्रिप प्रणाली द्वारा की जाती है।

पॉलीहाउस तकनीक के उपयोग

- विपरीत मौसम यानी बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी तैयार की जा सकती है तथा कम समय में नर्सरी तैयार होती है।
- ये संरचनाएं सब्जियों को ठण्ड, पाला, गर्मी और हवा से बचाती हैं।
- सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने में सहायक जिससे अगेती फसल लेकर ज्यादा भाव में बाजार में बेचा जा सकता है।
- अधिक मूल्य वाली सब्जियों का उत्पादन करना संभव।
- बेमौसमी सब्जी उत्पादन-खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर का वर्ष भर उत्पादन किया जा सकता है।
- सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी संभव।

7. सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है।
8. कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है।
9. सब्जियों की मोनोक्रॉपिंग को बढ़ाना यानी साल में कई बार फसल उगा सकते हैं, जिससे क्रापिंग इंटेंसिटी बढ़ती है।
पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन के लिए सब्जियों की उन्नत किस्में
टमाटर- पंत टी- 3, डी टी एच- 1, अविनाश- 2, डी ए आर एल- 304, एच वाई बी- 99, के-126, एन पी- 5002 और नवीन प्रमुख हैं।
शिमला मिर्च- केलिफोर्निया वंडर, अलंकार, भारत इन्दिरा, गोल्डन समर, हीरा, बाम्बी, ओरोबेली, तनवी और जैमिनी आदि प्रमुख हैं।
खीरा- जापानीज लौंग, ग्रीन, पूसा संयोग, प्वाइनसेट, रानी, फूले पराची और कसन आदि प्रमुख हैं।
खरबूजा- पंजाब संकर- 1 और दिसी आदि।
फ्रेंचबीन- पंत अनुपमा और पंतबीन- 2, पूसा पार्वती कटेडर आदि प्रमुख हैं।
करेला- पूसा दौ मौसमी और पूसा विशेष आदि प्रमुख हैं।
बैंगन- पूसा हार्डबिड- 5,6 और 9, पंत संकर, हिसार और श्यामल आदि प्रमुख हैं।
ग्रीन हाउस या पॉलीहाउस में सब्जियों

की नर्सरी का विकास तेजी से होता है। इसमें सब्जियों की विपरीत मौसम में नर्सरी तैयार करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। इसमें कम लागत वाले पॉलीहाउस में सब्जियों की नर्सरी जैसे- शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और बेलवाली सब्जियां जैसे- खीरा, लौकी, करेला, तोरई, चप्पन कहू एवं ककड़ी इत्यादि, की बेमौसमी अर्थात् सर्दी में नर्सरी पौध तैयार करके एक दो महीने अगेती फसल ली जा सकती है, जिसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इसके लिये बांस की खपच्ची, पोलिथीन शीट, सुतली से एक झोपड़ीनुमा ग्रीन हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सब्जियों की पौध दिसम्बर से जनवरी में तैयार की जा सकती है।

अगेती नर्सरी (पौध) से फायदे

- अधिक पैदावार
- बेमौसमी उत्पादन
- अच्छी गुणवत्ता
- कम पानी की आवश्यकता
- कम खरपतवार व आसान नियंत्रण
- स्वस्थ व समय पर पौध उत्पादन
- विपरीत परिस्थितियों से बचाव
- कीट व रोग नियंत्रण आसान।

इन बातों का रखें ध्यान

- केवल उन्नत और संकर किस्में ही

उगाएँ।

2. सही सब्जी की फसल और सही किस्म का चयन।

3. सब्जी की बिजाई से पहले पॉलीहाउस में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह मिला दें तथा जमीन को पांच प्रतिशत फोरमेलिन से उपचारित करें।

4. शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा आदि ज्यादा लाभदायक फसलें होती हैं।

पौध की प्रोपेगेशन ट्रे में तैयार करें

सब्जियों की पौध के लिये प्रोपेगेशन ट्रे जिसे प्रो ट्रे भी कहते हैं, का इस्तेमाल करें जो आमतौर पर 98 छेदों वाली होती है, इसमें कोकोपीट + परलेट + वर्मीकुलेट का 4:1:1 का मिश्रण लेकर ट्रे तैयार कर लें तथा बीज की बिजाई कर दें।

पॉलीहाउस के फायदे

- प्रत्येक बीज का बिना क्षति के अंकुरण।
- जड़ों का पूरा विकास एवं निकालने एवं रोपाई में सुविधाजनक।
- पौधों का विकास एक समान और स्वस्थ पौधों का तैयार होना
- कम समय में पौध का तैयार होना।
- पौध की बीमारियां कम।
- कीट नियंत्रण सरलता से किया जा



सकता है।

7. रोपाई उपरान्त कम मृत्युदर और पौधों का विकास जल्दी होना।

8. पॉलीहाउस को बागवानी के व्यावसायीकरण ने किसानों की एक खास जरूरत बना दिया है, जिसमें बेमौसमी सब्जियां उगाकर आमदनी को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।

9. परम्परागत कृषि विधियों की अपेक्षा पॉलीहाउस में सब्जियों को उगाने से खुले

वातावरण की तुलना में दो से चार गुणा तक अधिक पैदावार ली जा सकती है।

10. वर्ष भर सब्जी उत्पादन करना, साथ ही उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता तथा उत्पादकता में भी काफी बढ़ोतरी प्राप्त की जा सकती है।

11. पॉलीहाउस में पर-परागण वाली सब्जियों के बीजों को सरलता से तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार तैयार किए गए बीजों में वंश शुद्धता बनाये रखी जा

सकती है और यह बीज उच्च गुणवत्ता के होते हैं। पॉलीहाउस के अन्दर उगाई जाने वाली सब्जियों में वे सभी सस्य क्रियायें करनी पड़ती हैं, जिन्हें खुले खेत में करते हैं। गोबर की खाद का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिये। बीच-बीच में मिट्टी का निर्जीवीकरण करना आवश्यक होता है। जिसके लिये फार्मेलिडाइड और अन्य रसायन या प्लास्टिक शीट बिछाकर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है।

औषधीय पौधों की खेती

परंपरागत खेती का विकल्प बनी औषधीय फसलों की खेती, अच्छे मुनाफे से किसानों का रुझान बढ़ा

देश में कोरोना का दूसरी लहर में लाखों लोगों ने आयुर्वेद की औषधियों का सेवन करके स्वास्थ्य में लाभ पाया। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। कोरोना काल के समय देश-दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों ने अच्छा लाभ कमाया है। देश की कई नामी कंपनियां के आयुर्वेद उत्पाद विश्वभर में प्रसिद्ध हैं और सालभर उनकी मांग बनी रहती है। पोस्ट में किसान भाइयों को 5 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की जानकारी दी जा रही है। किसान भाई अपने क्षेत्र की जलवायु, मौसम और भूमि के आधार पर इनकी खेती कर सकते हैं। कई राज्यों में सरकार की ओर से सब्सिडी और अनुदान भी दिया जाता है।

भारत में पारंपरिक फसलें बनाम औषधीय फसलें

भारत के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के

उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूँ, चावल, मका, ज्वार, बाजरा, गन्ना,कपास, सरसों, मूँगफली आदि की बुवाई करते हैं। जबकि औषधीय फसलों में सर्पगन्धा, अश्वगंधा, ब्राम्ही, कालमेघ, कौंच, सतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वच, आर्टीमीशिया,लेमनग्रास, अकरकरा, सहजन प्रमुख हैं। परंपरागत फसलों की खेती की तुलना में औषधीय पौधों की खेती से एक हेक्टेयर में किसानों को ज्यादा आमदनी होती है।

खेती के लिए जरूरी है फसल विविधता

खेत में कई सालों तक एक ही तरह की फसल उगाने से पैदावार क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में खेत में फसल विविधता के लिए औषधीय खेती करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी जाती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेत की एक ही तरह की फसल लेने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। ऐसे में किसानों को फसल विविधता के लिए सलाह दी जाती है। फसल विविधता के इस क्रम में अगर गेहूँ और धान के खेतों को खाली होने के बाद अगर किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो यह उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगली बार जब वह

सहजन की खेती

सहजन में 90 तरह के मल्टी विटामिन्स, 45 तरह के एंटी ऑक्सीजेंट गुण और 17 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसलिए सालभर इसकी मांग बनी रहती है। कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खासियत यह है कि इसकी एक बार बुवाई के बाद चार साल तक बुवाई नहीं करनी पड़ती है। सहजन की खेती लगाने के 10 महीने बाद एक एकड़ भूमि में किसान एक लाख रुपए कमा सकते हैं। सहजन को ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इसका उपयोग सब्जी और दवा बनाने में होता है। देश के अधिकतर हिस्सों में इसकी बागवानी की जा सकती है। आयुर्वेद में इसके पत्ते, छाल और जड़ तक का उपयोग किया जाता है। करीब पांच हजार साल पहले आयुर्वेद ने सहजन की जिन खूबियों को पहचाना था, आधुनिक विज्ञान में वे साबित हो चुकी हैं। देश के अपेक्षाकृत प्रागतिशील दक्षिणी भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसकी खेती होती है।



अकरकरा की खेती

अकरकरा की खेती औषधीय पौधे के रूप में की जाती है। इसके पौधे की जड़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा बनाने में किया जाता है। पिछले 400 साल से उपयोग आयुर्वेद में इसका उपयोग हो रहा है। यह कई औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके बीज और डंठल की मांग बनी रहती है। इसका उपयोग दंतमंजन बनाने से लेकर दर्द निवारक दवाओं और तेल के निर्माण में होता है। अकरकरा की खेती कम मेहनत और अधिक लाभ देने वाली पैदावार है। अकरकरा की खेती 6 से 8 महीने की होती है। इसके पौधों को विकास करने के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में होती है। इसके पौधों पर तेजगर्मी गर्मी या अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पी.एच. मान सामान्य होना चाहिए।



समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में होती है।

इसके पौधों पर तेजगर्मी गर्मी या अधिक सर्दी का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पी.एच. मान सामान्य होना चाहिए।

सतावर की खेती

सतावर को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। सतावर एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए होता है। बीते कुछ वर्षों में इस पौधे की मांग बढ़ी है और इसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। किसान इसकी खेती से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सतावर की फसल जुलाई से लेकर सितंबर तक लगाई जाती है। सतावर की खेती से एक एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके पौधे को तैयार होने में करीब 1 साल से अधिक का समय लग जाता है। जैसे ही फसल तैयार होती है, वैसे ही किसानों को कई गुना ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है। सतावर की खेती इस लिए भी फायदे की खेती है कि इसमें कीट पतंग नहीं लगते। वहीं, कांटेदार पौधे होने की वजह से जानवर भी इसे नहीं खाते हैं। सतावर की खेती उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान में बड़े पैमाने पर होती है।

उसमें धान और गेहूँ उगाएंगे तो उसकी पैदावार अधिक होगी।

किसान को मालामाल करने वाली 5 औषधीय पौधों की खेती की जानकारी

देश-दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और जड़ी-बूटियों की तरफ भी अपना रुख कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला समय हर्बल उत्पादों का ही होगा। सरकार की तरफ से भी पारंपरिक फसलों की जगह अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें आयुर्वेद में दवाई बनाने में उपयोग होने वाली औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं।

लेमनग्रास की खेती

लेमनग्रास को आमभाषा में नींबू घास कहा जाता है। भारतीय लेमनग्रास के तेल में विटामिन ए और सिट्राल की अधिकता होती है। लेमनग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। लेमन ग्रास से निकले तेल को कॉस्मेटिक्स, साबुन और तेल और

दवा बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। यही वजह है कि किसानों का इस फसल की ओर रुझान भी बढ़ा है। किसान इसकी खेती करके मालामाल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इस पर आपदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसकी फसल को पशु नहीं खाते हैं, इसलिए यह रिस्क फ्री फसल है। इसकी रोपाई के बाद सिर्फ एक बार निराई करने की जरूरत पड़ती है, तो वहीं सिंचाई भी साल में 4 से 5 बार ही करनी पड़ती है। इसलिए इसकी काफी मांग बनी रहती है।

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे को पूरा करने की कवायद में जुटी भारत सरकार ने एरोमा मिशन के तहत जिन औषधीय और संगंध पौधों की खेती का रकबा बढ़ा रही है उसमें एक लेमनग्रास भी है।

लेमन ग्रास का पौधा लगाने के बाद यह लगभग छह महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद हर 70 से 80 दिनों पर किसान इसकी कटाई कर सकते हैं। साल भर में इस पौधे की पांच से छह कटाई की जा सकती है।

अश्वगंधा की खेती

यह एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। यह अन्य सभी जड़ी-बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके उपयोग तनाव और चिंता को दूर करने में किया जाता है। इसकी जड़, पत्ती, फल और बीज औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। किसानों के लिए अश्वगंधा की खेती बहुत लाभकारी है। किसान इसकी खेती से कई गुना अधिक कमाई कर सकते हैं, इसलिए इसे कैश क्राप भी कहा जाता है। अश्वगंधा को बलवर्धक, स्फूर्तिदायक, स्मरणशक्ति वर्धक, तनाव रोधी, कैंसररोधी माना जाता है। अश्वगंधा कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली औषधीय फसल है। अश्वगंधा की खेती कर किसान लागत का तीन गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य फसलों की अपेक्षा प्राकृतिक आपदा का खतरा भी इस पर कम होता है। अश्वगंधा की बोआई के लिए जुलाई से सितंबर का महीना उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान समय में पारंपरिक खेती में हो रहे नुकसान को देखते हुए अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

